• जयपुर, बुधवार, 3 जुलाई 24 • वर्ष 13 • अंक 305 • पृष्ठ : 8 • मूल्य : 1 रुपये
www.chamaktarajasthan.in| Email : chamaktarajasthan8789@gmail.com

डाक पंजीयन संख्या: RJ/JPC/D19/2024-25
RNI. No. RAJHIND/2011/40950

दैनिक
राज्य तथा केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त
सच के साथ मजबूती से बढ़ाये कदम

चमकता राजस्थान

जयपुर से प्रकाशित एवं प्रसारित
अजमेर, सीकर, झुंझनुं, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, धौलपुर, हिडौन, भरतपुर, झालावाड़, जोधपुर, बीकानेर से प्रसारित

विज्ञापन के लिए : 93145 05000

सुविचार

''सत्य को हज़ार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा।''
● स्वामी विवेकानंद

पेज @3 एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मादक पदार्थो के कुख्यात तस्कर महिपाल....
पेज @4 जयपुर उत्तर पुलिस ने स्मार्ट फोन के लॉक तोड़कर ईएमईआई नंबर...
पेज @8 » वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रवीण गुप्ता बने सार्वजनिक...

हाथरस भगदड़ : 80 से अधिक की मौत, उच्चस्तरीय जांच के आदेश

हाथरस । एजेंसी

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र स्थित रतिभानपुर में सत्संग के बाद मची भगदड़ में अबतक 80 से अधिक लोगों की जान चली गई है। हादसे में एटा जिला अस्पताल में 27 और सीएचसी सिकंदराराऊ में 50-60 लोगों के शव लाए गए हैं। जिलाधिकारी आशीष कुमार ने कहा कि हादसे में 50 से 60 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। घटना को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के मुगलगढ़ी एक गांव में सत्संग के बाद जब लोग बाहर निकलने लगे तो भगदड़ मच गई। हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मीडिया कर्मियों ने जब पूछा कि एटा में 27 लोगों के शव लाए गये हैं तो हादसे में कितने लोगों की जान गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि यहां की सीएचसी के डॉक्टरों ने मुझे 50-60 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया है।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति एसडीएम ने दी थी और यह एक निजी आयोजन था। मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है। प्रशासन की प्राथमिकता घायलों और मृतकों के परिजनों को हरसंभव मदद मुहैया कराना है।

एटा जिला अस्पताल में 27 और सीएचसी सिकंदराराऊ में 50-60 शव लाये गये : जिलाधिकारी

दो मंत्रियों के साथ चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी पहुंचे मौके पर

लखनऊ/एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे को देखते हुए सरकार के दो मंत्रियों चौधरी लक्ष्मीनारायण, संदीप सिंह और मुख्य सचिव व डीजीपी को मौके पर भेजा है। मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा 'जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं।'

मुख्यमंत्री ने की मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा

घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा

लखनऊ/एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जांच के आदेश देने के साथ मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। हाथरस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं पल-पल की जानकारी ले रहे हैं। पूरे घटनाक्रम पर वह सीधी नजर रखे हुए हैं। योगी ने एडीजी, आगरा और कमिश्नर, अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। कार्यक्रम आयोजकों के विरुद्ध एफआईआर होगी। शासन आयोजकों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हाथरस हादसे पर जताया दुःख

नयी दिल्ली । एजेंसी

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये, घायलों को 50 हजार रुपये दिये जाएंगे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित सत्संग के दौरान मची भगदड़ की घटना पर गहरा दुःख जताया है। राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिवारजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर जारी शोक संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई जनहानि के बारे में जानकर बहुत व्यथित हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के दौरान घटना पर शोक जताते हुए कहा कि राज्य सरकार, प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उप्र सरकार के लगातार संपर्क में हैं।

न्यूज़ अपडेट

राहुल गांधी के लोकसभा में भाषण के विवादास्पद अंश हटाए गए

नई दिल्ली/एजेंसी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण के कुछ विवादास्पद अंश हटा दिए गए हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में भाषण दिया था। हटाए गए अंश में हिंदुओं और कुछ दूसरे धर्मों पर उनकी टिप्पणियां शामिल हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) के रूप में राहुल गांधी का सोमवार को पहला भाषण था। इस दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद ने संविधान की एक प्रति और भगवान शिव की तस्वीर लहराई और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा। राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं का उल्लेख करने पर भाजपा सांसदों ने कड़ा विरोध किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान हस्तक्षेप किया।

आईएएस अमित किशोर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव नियुक्त

नई दिल्ली/एजेंसी। आईएएस अधिकारी अमित किशोर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस बाबत पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि किशोर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सह-अवधि के आधार पर या जब तक वह इस पद पर कार्य करना बंद नहीं कर देते, राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में कार्य करेंगे। यूपी कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अमित किशोर यूपी के देवरिया जिले के जिलाधिकारी रहने के साथ-साथ एटा जिले के डीएम रह चुके हैं। उसके बाद बाद उनका तबादला बतौर एमडी, साउथर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कार्पोरेशन में हुआ था। इससे पहले यूपी कैडर के 2007 बैच के अधिकारी आलोक तिवारी सितंबर 2021 से रक्षा मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे।

तीन दिनों में 51,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा अमरनाथ के दर्शन

जम्मू/एजेंसी। 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के बाद से अब तक 51,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंगलवार को 6,537 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था दो सुरक्षा काफिले के साथ कश्मीर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 6,537 तीर्थयात्री जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुए। अधिकारियों ने बताया, इनमें से 2106 श्रद्धालु 105 वाहनों के सुरक्षा काफिले के साथ सुबह 3.05 बजे बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए, जबकि 4,431 तीर्थयात्री 156 वाहनों में सवार होकर सुबह 3.50 बजे नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप के लिए रवाना हुए।

महाराष्ट्र पासपोर्ट रैकेट मामले में सीबीआई ने की छापेमारी, 1.59 करोड़ रुपये जब्त

मुंबई/एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को एक पासपोर्ट एजेंट के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में टीम ने 1.59 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं। सीबीआई ने यह छापेमारी पिछले हफ्ते पकड़े गए इस बड़े घोटाले की जांच के सिलसिले में की है। छापेमारी में पांच डायरियां और डिजिटल गैजेट भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
सीबीआई ने पिछले वीकेंड महाराष्ट्र में 33 स्थानों पर छापेमारी की और रिश्वत के बदले संदिग्ध पासपोर्ट जारी करने के कथित रैकेट में 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
सीबीआई ने शिकायतों के बाद नासिक के अलावा मलाड और लोअर परेल स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) के 14 पासपोर्ट विभाग अधिकारियों के खिलाफ मुंबई तथा नासिक में 12 केस दर्ज किए और मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की।

सिद्धू मूसेवाला के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की करनी थी हत्या

मुंबई/एजेंसी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पनवेल पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में इस बात के संकेत मिले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू मूसेवाला की तरह सलमान खान की भी हत्या करना चाहती थी। नवी मुंबई पुलिस के अनुसार, अभिनेता सलमान खान की हत्या के प्रयास के मामले की जांच कर रही नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के पांच गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी पाकिस्तान से एके-47 राइफल, एके-92 राइफल और एम-16 राइफल खरीदने की तैयारी कर रहे थे और जिगाना पिस्तौल भी जिससे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। नवी मुंबई पुलिस का कहना है कि बिश्नोई गिरोह ने अभिनेता की हत्या के लिए 25 लाख रुपये की सुपारी देने की घोषणा की थी। खास बात है कि पुलिस की तरफ से बीते सप्ताह दाखिल चार्जशीट में हमले की योजना और बचकर भागने के रास्ते शामिल हैं।

चाय वाले का प्रधानमंत्री बनना हजम नहीं कर पा रही कांग्रेस, एनडीए सांसद राहुल गांधी की तरह पेश न आएं : मोदी

नई दिल्ली/एजेंसी।

संसद में संग्राम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को संसदीय नियमों और संसदीय आचरण का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष एक गैर कांग्रेसी नेता का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एनडीए सांसदों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष इस बात से परेशान है कि पहली बार एक गैर-कांग्रेसी नेता, वह भी एक चायवाला, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। संसदीय दल की बैठक में मोदी ने सांसदों को सदन में अपना आचरण ठीक रखने की नसीहत दी।

सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सांसदों से कहा कि वे लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह पेश न आएं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने राजग सांसदों को बताया कि हमें सदन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने गैर-जरूरी बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष विशेषकर कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ ?लोग बेचैन हो गए हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीन बार जीत हासिल नहीं कर सका, जोकि एक चाय बेचने वाले ने हासिल की थी।
प्रधानमंत्री ने नए सांसदों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संसद की कार्यवाही में हिस्सा लें। अपने लोकसभा क्षेत्र के विषयों को उठाएं। सभी सांसदों को देश सेवा को सर्वोपरि रखना है। सांसदों को अपना व्यवहार और आचरण ठीक रखना चाहिए। साथ ही साथ सांसदों को संसद के नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए। संसद सदस्यों को जिन विषयों पर विशेष रुचि है, उसको साझा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर सांसद को परिवार सहित प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाना चाहिए। हर सांसदों को अपने जड़ से जुड़ा रहना चाहिए। इधर-उधर भाषण की बजाए बेहतर ढ़ंग से अपनी बात उचित फोरम पर रखना चाहिए।
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक परिवार से कई प्रधानमंत्री बने और कुछ सुपर प्रधानमंत्री बने। उन्हें एक चाय वाले का प्रधानमंत्री बनना हजम नहीं होता इसलिए वो बार-बार हम पर हमला करते हैं।

पुणे में जीका वायरस के 6 केस आए सामने, संक्रमितों में दो गर्भवती महिलाएं भी शामिल

पुणे/एजेंसी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में जीका वायरस के केस मिलने से हड×कंप मच गया है। पुणे में जीका वायरस संक्रमण के छह मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि जीका वायरस के इन 6 मरीजों में से दो गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल, जीका वायरस संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर की इसी प्रजाति को डेंगू और चिकनगुनिया जैसे संक्रमण फैलाने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है।

अधिकारियों ने कहा कि एरंडवाने इलाके की 28 वर्षीय गर्भवती महिला में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया। शुक्रवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 12 सप्ताह की गर्भवती एक अन्य महिला में भी सोमवार को संक्रमण पाया गया। दोनों महिलाओं की हालत अभी ठीक है और उनमें कोई लक्षण नहीं है। बता दें कि गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस के कारण भ्रूण में माइक्रोसेफेली हो सकता है। जीका वायरस संक्रमण का पहला मामला एरंडवाने में सामने आया, जहां 46 वर्षीय डॉक्टर की रिपोर्ट सकारात्मक आई थी।

कर्तव्य का महामंत्र | **प्रधानमंत्री मोदी ने दिया एनडीए सांसदों को महामंत्र, कहा-**

सांसदों का प्रथम दायित्व देश सेवा है : मोदी

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को अपनी सरकार के तीसरे कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संसद पुस्तकालय भवन के जीएमसी बालयोगी सभागार में संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को उनके कर्तव्य निर्वहन का महामंत्र दिया। उन्होंने कहा, सांसदों का प्रथम दायित्व देशसेवा है। यह बैठक करीब एक घंटे तक चली।

बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। एनडीए के सभी साथियों ने उनका फूल माला से अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को देश की सेवा करने, संसद में नियमों के आधार पर आचरण करने के साथ कई मंत्र दिए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने मीडिया को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने सभी सासंदों का देश की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को शुभकानाएं देते हुए कहा कि सांसद किसी भी दल के हों, उनके लिए देश की सेवा प्रथम दायित्व है। देश को ऊपर रख कर काम करना है।

किरण रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सासंदों के संसद में आचरण पर भी मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री ने हर एक सासंद को अपने -अपने क्षेत्र के विषय को प्रभावी तरीके से रखने के साथ नियम के मुताबिक आचरण करने की सलाह दी। इसके साथ उन्होंने संसादों को अपनी-अपनी रुचि में महारत विकसित करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री ने एनडीए के सभी सांसदों से आग्रह किया है कि वे सदन के नियमों और लोकतंत्र की परंपरा के अनुरूप आचरण करें। खासकर पहली बार चुन कर आए सांसदों को सदन के नियमों के अनुरूप आचरण करने का मंत्र दिया।

बेवजह बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी

उन्होंने कहा कि अच्छा सांसद बनने के लिए नियमों की जानकारी के साथ तथ्यों के साथ अपनी बातों को सदन में रखना चाहिए। किरण रिजिजू ने बताया कि बैठक में एनडीए के सभी दलों के बीच अच्छा समन्वय देखने को मिला। बैठक में एनडीए के सभी साथी सम्मलित हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सासंदों से परिवार सहित प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसदों को देश के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को जानना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इसके साथ सासंदों को बेवजह बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी।

छह दिन पहले ही पूरे देश में पहुंचा दक्षिण-पश्चिम मानसून

अगले पांच दिनों तक पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

एजेंसी

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से छह दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच गया है। भारत मौसम विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून ने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों में आगे बढ़ते हुए मंगलवार को ही पूरे देश को कवर कर लिया है। यह सामान्य रूप से आठ जुलाई तक पूरे देश में पहुंचता है। कई राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने बताया कि अगले पांच दिनों तक पूरे उत्तर भारत में भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 05 और 06 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली में 02 और 03 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पंजाब में 3 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में 02 जुलाई से 6 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ गुजरात, उप हिमालय पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 02 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि मानसून केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 30 मई को पहुंचा था, जो सामान्य से दो से छह दिन पहले है। महाराष्ट्र तक पहुंचने के बाद मानसून की गति धीमी हो गई, जिसके कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मानसून आने में देरी हुई। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को प्रेसवार्ता में कहा कि जुलाई में भारत में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। भारी बारिश के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और देश के मध्य भाग में नदी-घाटियों में बाढ़ आने की संभावना है।

समाचार वाचिका डॉ शीला मेहरा, सलमान रुश्दी जैसों को मिले न्याय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पटना हाई कोर्ट के 100 साल पूरा होने के मौके पर देश की अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी। यह बात 2016 की है। वे जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तब देश के चोटी के वकील, जज और अन्य गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। सारा देश जानता है कि देश की निचली से लेकर उच्चतम न्यायालयों तक में मामलों की संख्या लाखों–करोड़ों हो चुकी है और बढ़ती ही चली जा रही है। इस कारण न्याय पाने वालों को अभूतपूर्व देरी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी तीसरी पारी में मोदी लंबित मामलों से जूझ रही देश की न्याय व्यवस्था में सुधार करेंगे।

अगर यह होता है तो डॉ. शीला मेहरा जैसे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। देवकी नंदन पांडे, विनोद कशय्प और अशोक वाजपेयी जैसे दिग्गज हिन्दी न्यूज रीडरों के साथ, डॉ. शीला मेहरा ने ऑल इंडिया रेडियो से दशकों तक देश–दुनिया को अपनी धीर–गंभीर आवाज में खबरें सुनाई हैं। भारत की कई पीढ़ियों ने इन सबकी गहरी आवाज और स्पष्ट उच्चारण में खबरों को पढ़ते हुए सुना है। जिन दिनों रेडियो की मार्फत देश समाचार सुनता था, तब डॉ. शीला मेहरा किसी सेलेब्रिटी से कम नहीं थीं। लगभग एक दशक पहले सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद, उनका जीवन बदल गया। उसके बाद वो अपने पति आर.के. मेहरा के साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के धक्के खाने लगीं। कारणः मेहरा दंपति ने गाजियाबाद में 25 हजार रुपये में जमीन खरीदी थी। यह 1970 के दशक के शुरुआत की बात है। इनकी तरह कई अन्य लोगों ने भी गाजियाबाद में जमीनें खरीदी थीं। दिल्ली के कोलाहल से दूर घर बनाने की उनकी उम्मीद 1975 में जीडीए द्वारा उनकी जमीन अधिग्रहण करने के साथ ही चकनाचूर हो गई। उस समय जीडीए को आवास विकास के नाम से जाना जाता था। जीडीए ने अधिग्रहीत जमीन पर बाद में प्रताप विहार को विकसित किया, लेकिन उन सभी किस्मत के मारे लोगों को एक पैसा भी नहीं मिला जिनकी जमीन अधिग्रहीत की थी। वे सब के सब नौकरीपेशा लोग थे।

अपने भाग्य को कोसने के बजाय, डॉ. शीला मेहरा, उनके पति और बाकी लोग अपनी अधिग्रहीत जमीन का उचित और न्यायसंगत मुआवजा पाने के लिए जीडीए से लड़ रहे हैं। मेहरा दंपति ने 2 फरवरी, 1978 को गाजियाबाद की निचली अदालत में मुकदमा दायर किया ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। उन्हें और शेष लोगों को जीडीए के शीर्ष अधिकारियों से आश्वासन के अलावा, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। वे अपने वकीलों को फीस दे रहे हैं, हालांकि उनकी आय के स्रोत बहुत कम हैं। कब जीडीए से मुआवजा पाने के लिए लड़ रहे लोगों को न्याय मिलेगा? जीडीए जैसे विभागों के कामकाज को जानने वाले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश से सैकड़ों असहाय लोगों को उनका हक मिल सकता है। जब इन लोगों को जीडीए से न्याय नहीं मिला तो इन्होंने गाजियाबाद की निचली अदालत में 1978 मुकदमा दायर किया था। इन्हें अदालत से नियमित तौर पर तारीखें मिलती हैं। अदालत की तारीख के दिन, पांच लोगों को वहां मौजूद रहना होता है। यह हैं– केस के जज, मुकदमे के वादी, उनके वकील, जीडीए के वकील और जीडीए के अधिकारी। पर अफसोस कि ये सब तारीख वाले दिन कभी मिल नहीं पाते। कोई न कोई जरूर ही गैर–हाजिर रहता ही है जिससे मामला टलता ही जाता है।

यह गंभीर चिंता का विषय है कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ को पार कर गई है, जैसा कि 20 जुलाई, 2023 को राज्यसभा को बताया गया। देश के तब के विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, 25 उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 5.02 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। भारत में 2022 में जजों की स्वीकृत संख्या प्रति दस लाख आबादी पर 21.03 की थी। जजों की कुल स्वीकृत संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 34, उच्च न्यायालयों में 1108, और जिला अदालतों में 24,631 थी। भारत के विधि आयोग और न्यायमूर्ति वी एस मलीमथ की समिति ने जजों की संख्या प्रति दस लाख आबादी पर 50 तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। जजों की स्वीकृत संख्या निर्धारित होने के बावजूद, भारत की अदालतों ने जजों की रिक्ति के कारण काफी समय से पूरी क्षमता में काम नहीं किया है। एक विचार यह भी है कि अदालतों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार का अदालतों में मामलों के निपटान में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें भी मामलों के निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि उत्तर प्रदेश के तेजतर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीडीए को निर्देश दें तो मुआवज़ा चाहने वालों को तुरंत न्याय मिल सकता है। इससे डॉ. शीला मेहरा जैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है।

पिछली 17 फरवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था, ₹निचली अदालतें ही हैं जहां समस्याओं का समाधान शुरू होता है, वहां ध्यान देने की आवशय़कता है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई मामले बढ़ रहे हैं जो खुद निचली अदालत में ही निपटने चाहिए।₹ लेखक सलमान रुश्दी की दिल्ली के पॉश एरिया फ्लैग स्टाफ रोड में पैतृक संपत्ति का कोर्ट में बीती आधी सदी से चल रहा कानूनी विवाद इस बात की चीख–चीख कर पुष्टि करता है कि हमारे यहां कोर्ट के रास्ते से न्याय पाना कितना कठिन और थकाने वाली प्रक्रिया है। बेशक, भारत की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है न्याय मिलने में होने वाली अभूतपूर्व देरी। इस तरफ तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। जरा सोचिए कि जब सलमान रुश्दी जैसी अंतरराष्ट्रीय शख्सियत को न्याय के लिए इतना जूझना पड़ रहा है, तो आम इनसान की कोर्ट में क्या हालत होती होगी। हमारे यहां कहा ही जाता है कि किसी को प्रताड़ित करना है तो उसे किसी कानूनी केस में फंसा दो या फिर पुरानी यानी सेकेंड हैंड कार दिलवा दो। आप देश के किसी भी भाग में निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर देख लें। वहां पर आपको इंसाफ के लिए जूझते बेबस लोग मिलेंगे। 'न्याय में देरी, न्याय से वंचित होना' एक पुरानी कहावत है। अब समय आ गया है कि डॉ. शीला मेहरा और सलमान रुश्दी जैसे करोड़ों लोगों को सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान किया जाए।

नये भारत में बदलाव के कानून, न्याय की ओर

ललित गर्ग

भारतीय न्याय प्रणाली की कमियां को दूर करते हुए उसे अधिक चुस्त, त्वरित एवं सहज सुलभ बनाना नये भारत की अपेक्षा है। मतलब यह सुनिश्चित करने से है कि सभी नागरिकों के लिये न्याय सहज सुलभ महसूस हो, कानूनी प्रावधान न्यायसंगत एवं अपराध–नियंत्रण का माध्यम हो, वह आसानी से मिले, जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त होकर सस्ता हो। निश्चित रूप से किसी भी कानून का मकसद नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति व अधिकारों की रक्षा करना ही होता है। जिससे किसी सभ्य समाज में न्याय की अवधारणा पुष्ट हो सके। 1 जुलाई, 2024 से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। न्याय का एक नया सूरज उदित हो रहा है, जब पूरे देश में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य संहिता को लेकर उम्मीद करनी चाहिए कि यह बदलाव न्याय की कसौटी पर खरा उतरेंगे। इस दृष्टि से यह कानून से जुड़ी अकल्पित उपलब्धियों से भरा–पूरा अवसर भारत न्याय प्रक्रिया को एक नई शक्ति, नई ताजगी और नया परिवेश देने वाला साबित होगा। उल्लेखनीय है कि कानूनी बदलाव से जुड़े ये तीनों विधेयक बीते साल संसद में पारित किये गए थे। अंग्रेजों के बनाये कानून क्या स्वतंत्र भारत में साढ़े सात दशक बाद भी लागू रहने चाहिए, यह लम्बे समय से विमर्श का विषय बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी, आधुनिक, तकनीकी बनाने के लिये, अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को बदलने एवं आधुनिक अपेक्षाओं के नये कानून बनाने का साहसिक एवं प्रासंगिक कदम उठाते हुए नए कानून लाने एवं उन्हें लागे करने का बड़ा कदम उठाया है, जो सुखद एवं स्वागतयोग्य है। विपक्षी दलों ने सांस्कृतिक, धार्मिक व भौगोलिक विविधता वाले देश के लिये बनाये गये कानूनों को भले ही व्यापक सार्वजनिक विमर्श के बाद ही लागू किया जाने की अपेक्षा व्यक्त की हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जहां ब्रिटिश काल में बने कानूनों का मकसद दंड देना था, वहीं नये कानूनों का मकसद नागरिकों को न्याय देना है। मौजूदा चुनौतियों व जरूरतों के हिसाब से कानूनों को बनाया गया है।

इन कानूनों को बनाने का मूल उद्देश्य अपराधमुक्त समाज की संरचना करना है। इसीलिये अपराधियों को कड़े दण्ड देने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता में विवाह का प्रलोभन देकर छल के मामले में दस साल की सजा, किसी भी आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा, लूटपाट व गिरोहबंदी के मामले में तीन साल की सजा का प्रावधान है। आतंकवाद पर नियंत्रण के लिये भी कानून है। किसी अपराध के मामले में तीन दिन में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा सुनवाई के बाद 45 दिन में फैसला देने की समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं प्राथमिकी अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिये दर्ज की जाएगी। व्यवस्था की गई है कि लोग थाने जाए बिना भी ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कर सकें। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इन कानूनों के माध्यम से देश में पुलिस सुधार को भी बल मिलेगा। पुलिस कानून–कायदे के तहत काम करने को विवश या बाध्य होगी। अंततः अब पुलिस को अनुशासित बनाने के साथ–साथ कारगर बनाने की ओर देश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पुलिस प्रशासन की सफलता इसी में है कि तमाम लोगों को यह महसूस हो कि कानून न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जा रहा है। एक पहलू यह भी है कि पुलिस प्रशासन को कुशल और सक्षम बनाने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आए। जिस स्तर की सेवा की उम्मीद लोग पुलिस से कर रहे हैं, उसके लिए सरकारों को पुलिस पर व्यय बढ़ाना होगा। सक्षम और सहयोगी पुलिस हमारे तेज विकास में कारगर होगी। पुलिस को प्रशिक्षित एवं सक्षम बनाने के तंत्र भी नये तरीके से विकसित करने होंगे। एक तरह से इन कानूनी प्रावधानों को सहज एवं सरल बनाने के प्रयास किये गये हैं।

ध्यान रहे, पिछले कानूनों में यह बड़ी कमी थी कि वे गरीबों को न्याय दिलाने में असमानता के द्योतक थे। उन कानूनों का इस्तेमाल गरीबों के खिलाफ जितनी आसानी से होता था, उससे कहीं ज्यादा कठिनाई से अमीरों के खिलाफ मामले दर्ज होते थे। आरोप सिद्ध होने या सजा के मामले में भी गरीबों को ही ज्यादा भुगतना पड़ता था। औपनिवेशिक युग के निर्मम या गरीब विरोधी कानूनों को समाप्त करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। अब इन नये तीन कानूनों ने ब्रिटिश काल के तीन कानूनों की जगह ले ली है, इसका एहसास कराना होगा कि ब्रिटिश हिसाब से बने कानून अब देश में नहीं चल रहे हैं। नए कानूनों में यह ताकत है कि इनसे अपने यहां संपूर्ण न्याय प्रणाली में आम नागरिकों के अनुरूप आधुनिक बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है और अब राज्यों को अपने स्तर पर इन अच्छे एवं प्रभावी कानूनों को लागू करने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और देश के ज्यादातर राज्यों में पुलिस जिस तरह से प्रशिक्षित हो रही है, इससे जुड़ी खबरों का सामने आना भी सुखद है। सक्षम और सहयोगी पुलिस नये भारत–सशक्त भारत–विकसित भारत में कारगर होगी।

सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुरूप राजद्रोह कानून को तो हटा दिया गया है लेकिन राष्ट्रीय एकता, अखंडता व संप्रभुता के अतिक्रमण को नये अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संगठित अपराधों के लिये तीन साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही अपराध की जांच–पड़ताल को आधुनिक तकनीक के जरिये न्यायसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। जिसमें फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना भी अनिवार्य है ताकि अपराधी संदेह का लाभ न उठा सकें। दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अपराध नियंत्रण में बढ़ेगा। नये कानून के अनुसार मौत की सजा पाये अपराधी को खुद ही दया याचिका दायर करनी होगी, कोई संगठन या व्यक्ति ऐसा न कर सकेगा। निश्चित ही जहां सरकार वर्तमान संदर्भ के अनुरूप कानूनों का आधुनिकीकरण कर रही है वहीं उसे कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने एवं पुलिस–व्यवस्था को सुधारने एवं सक्षम बनाने के लिये साधन–सुविधाओं को सुलभ कराने के लिये तत्पर होना होगा।

नये कानून एवं नयी आधुनिक अदालते कल के भारत को और मजबूत करेगी। नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने में इनकी सर्वाधिक सार्थक भूमिका होगी। सरकार अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी या स्थानीय भाषाओं में न्याय–प्रक्रिया को संचालित करने के लिये भी प्रतिबद्ध है। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। एक जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले तीन नये कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआइआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नये कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआइआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान होगा।

शिकायत, सम्मन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रानिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। उपर्युक्त सभी बातों को देखते हुए स्पष्ट है कि भारतीय न्याय तंत्र में विभिन्न स्तरों पर सुधार की दरकार को महसूस करते हुए वैसी व्यवस्थाएं की गयी है। लेकिन यह सुधार न सिर्फ न्यायपलिका के बाहर से बल्कि न्यायपालिका के भीतर भी होने चाहिये। ताकि किसी भी प्रकार के नवाचार को लागू करने में न्यायपालिका की स्वायत्तता बाधा न बन सकें। न्यायिक व्यवस्था में न्याय देने में विलंब न्याय के सिद्धांत से विमुखता है, अतः न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि दिखना भी चाहिये। नये कानूनों एवं नयी कानूनी व्यवस्थाओं से ऐसा होता हुआ दिख रहा है जो नये भारत की ओर गति को दर्शा रहा है।

पर्यावरण व स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक का उपयोग रोकना जरूरी

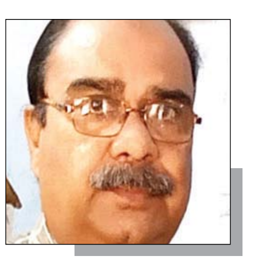

रजत मुखर्जी

कभी प्लास्टिक को बहुमुखी उपयोग और स्थायित्व के कारण क्रांतिकारी सामग्री के रूप में सराहा गया था। मगर, अब प्लास्टिक एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंता बन गया है। विश्व प्लास्टिक दिवस हमें प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। प्लास्टिक के व्यापक उपयोग ने हमारे ग्रह और इसके निवासियों को प्रभावित करने वाली कई समस्याओं को जन्म दिया है। इस निबंध में, हम प्लास्टिक के उपयोग से बचने के कारणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें इसके पर्यावरणीय प्रभाव, स्वास्थ्य संबंधी खतरे और वन्यजीवों के लिए दुखद परिणाम शामिल हैं।

प्लास्टिक से बचने का मुख्य कारण इसका पर्यावरणीय प्रभाव है। प्लास्टिक जैव–अविनाशी है, जिसका अर्थ है कि यह स्वाभाविक रूप से विघटित नहीं होता है। इसके बजाय, यह छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, जो सदियों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक मिट्टी और पानी को प्रदूषित करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा, प्लास्टिक का उत्पादन ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान देता है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है। प्लास्टिक उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों के निष्कर्षण और प्रसंस्करण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। पर्यावरणीय गिरावट के अलावा, प्लास्टिक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करता है। कई प्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए (बीपीए) और फाथेलेट्स जैसे हानिकारक रसायन होते हैं, जो भोजन और पेय पदार्थों में प्रवेश कर सकते हैं। ये रसायन एंडोक्राइन व्यवधानक के रूप में जाने जाते हैं, जो हार्मोनल कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं और प्रजनन समस्याओं और विकासात्मक विकारों सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा, जब प्लास्टिक कचरे को जलाया जाता है, तो यह जहरीले धुएं छोड़ता है जो मनुष्यों में श्वसन समस्याओं और अन्य गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का कारण बन सकते हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण के सबसे दिल दहला देने वाले परिणामों में से एक इसका वन्यजीवों पर प्रभाव है। जानवर, विशेष रूप से समुद्री जीव, अक्सर प्लास्टिक के मलबे को भोजन समझ लेते हैं। कछुए, उदाहरण के लिए, प्लास्टिक बैगों को जेलिफ़िश समझ कर खा लेते हैं। पक्षी, मछली, और समुद्री स्तनधारी प्लास्टिक कचरे को निगलते या उसमें उलझ जाते हैं, जिससे चोट, भूख और मौत हो जाती है। अध्ययनों से पता चला है कि 90% से अधिक समुद्री पक्षियों के पेट में प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक का सेवन आंतरिक चोटों, रुकावटों और भूख का कारण बन सकता है, क्योंकि जानवर प्लास्टिक को पचा या निकाल नहीं सकते, जिससे धीमी और दर्दनाक मौत हो जाती है।

अतः, प्लास्टिक के उपयोग से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व प्लास्टिक दिवस इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का समय है कि हम सभी को मिलकर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण और स्वस्थ और सुरक्षित रह सके।

नेपाल में राजनीति की बलिहारी

मुकुंद

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता अब सामान्य घटना हो गई है। नेपाल में 2008 में लोकतंत्र की स्थापना के बाद से चार बार राष्ट्रीय चुनाव हो चुके हैं। वहां अब तक 12 से ज्यादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दुर्भाग्य से कोई भी सरकार पांच साल की अवधि पूरी नहीं कर पाई। मौजूदा वामदल वाली सरकार का हश्र भी यही हुआ। इस सरकार में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और केपी शर्मा ओली की एमाले दो धुर विरोधी समूह शामिल रहे। इनके बीच शक्ति और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर लगातार खींचतान जारी रही। आखिरकार वही हुआ, जिसकी आशंका थी। यह गठबंधन टूट गया और ओली फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।

कोई महीनाभर से पहले प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 18 महीने के भीतर चौथी बार संसद के पटल पर विश्वासमत सिद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। 13 मई को उपप्रधानमंत्री उपेंद्र यादव के समूह वाली जनता समाजवादी पार्टी आपसी फूट के चलते प्रचंड सरकार से अलग हो गई थी। प्रधानमंत्री प्रचंड ने संविधान की धारा 100(2) के अंतर्गत विश्वासमत का प्रस्ताव रखा। यह 157 मतों के साथ बहुमत से पारित हो गया।

इससे पहले नेपाल में 2022 में प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व में वामदल वाली सरकार बनी जरूर पर वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। फिर प्रचंड ने प्रजातांत्रिक पार्टियों के साथ मिलकर दूसरी बार सरकार बनाई। इसमें नेपाली कांग्रेस भी शामिल थी। यह सरकार भी अधिक दिन तक नहीं टिक सकी। तीसरी बार प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एमाले), रवि लामिछाने की स्वतंत्रता पार्टी और उपेंद्र यादव की जनता समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। यह सरकार मई में उपेंद्र यादव के इस्तीफे के चलते संवैधानिक संकट में आई।

अब ओली फिर देश की कमान संभालने वाले हैं पर राजनीतिक स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है। नेपाल की राष्ट्रीय सभा में 275 सदस्य होते हैं। इसमें 165 सदस्य सीधे चुनकर आए हैं, उनमें से प्रचंड की माओवादी केंद्र के पास कुल 32 और एमाले के पास 78 सीटें हैं। एमाले ओली की पार्टी है। अतीत को देखें तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद से ही लगातार राजनीतिक अस्थिरता है। नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम का अध्ययन करने पर पता चलता है कि स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय लोकतंत्र की स्थापना के कुछ समय बाद ही राजनीतिक अस्थिरता के उभरने के कारण लोकतंत्र विफल हो गया। सनद है कि नेपाल में नब्बे के दशक में माओवादियों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए नए संविधान की मांग करते हुए हथियार उठा लिए थे। एक दशक तक चले गृहयुद्ध का अंत 2006 में शांति समझौते के साथ हुआ था। इसके दो साल बाद संविधान सभा के चुनाव में माओवादियों की जीत हुई। इसी के साथ 240 साल पुरानी राजशाही का अंत हो गया। मगर मतभेद और मनभेद की वजह से संविधान सभा नया संविधान नहीं बना सकी और कार्यकाल का कई बार विस्तार करना पड़ा। आखिरकार 2015 में एक संविधान को स्वीकृति मिल पाई। नेपाल में लोकतंत्र बहाल हो गया पर लगातार अस्थिरता बनी रही। वह आज भी जारी है। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से भी समझ आती है। किसी भी प्रधानमंत्री ने पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसका बड़ा कारण सिद्धांतों के बजाय सत्ता के लिए भूख है। नेपाल में आज की राजनीति का सबसे बड़ा सच है।

देश में कम आयुवर्ग की बच्चियों का विवाह रोकने में कई एजेंसियों ने किया है काम

डॉ. निवेदिता शर्मा

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कुछ समय पहले ही आई है, जिसके आंकड़े बता रहे हैं कि वैश्विक अनुमान के अनुसार करोड़ों लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। इनमें से एक तिहाई मामले अकेले भारत के हैं। भारत को लेकर रिपोर्ट कहती है कि 20 करोड़ से अधिक महिलाओं का विवाह बचपन में ही हो गया था। विश्व स्तर पर सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 के अनुसार, पांच में से एक लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, जबकि 25 वर्ष पहले यह संख्या चार में से एक थी। इस सुधार ने पिछली तिमाही सदी में लगभग 68 करोड़ बाल विवाहों को रोके जाने पर विभिन्न एजेंसियों ने काम किया है।

इन प्रगतियों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दुनिया लैंगिक समानता के मामले में पीछे रह गई है। लैंगिक असमानता के क्षेत्र में भी चुनौतियां व्याप्त हैं। सर्वेक्षण वाले 120 देशों में से लगभग 55 प्रतिशत देशों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर पाबंदी लगाने वाले कानून नहीं हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और कई महिलाओं के लिए उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के मामले में स्वायत्तता की कमी जैसे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। मौजूदा गति से, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रबंधन पदों में समानता हासिल करने में 176 साल लगेंगे। अब इस संपूर्ण रिपोर्ट में विचार करें भारत कहां और किस स्थिति में है। इसलिए यहां विषय भारत के संदर्भ में इस वैश्विक रिपोर्ट की गहराई से पड़ताल करने की है।

भारत के लोगों को भी यह देखना चाहिए कि आखिर यह इतनी बड़ी जनसंख्या बेटियों की जो 18 साल से कम है, वह जनसंख्या किस समाज के द्वारा सबसे अधिक बढ़ाई गई या जा रही है। हालांकि अनेक सरकारी एजेंसियां एवं पुलिस विभाग समेत स्वयंसेवी संस्थाएं भी यह लगातार चिंता करती हैं और बाल विवाह के रोकथाम के लिए भारत में सक्रिय हैं। यह भी सच है कि इनके संयुक्त प्रयासों से विवाह बहुत बड़ी संख्या में रुकते भी हैं, किंतु इसके बाद भी यदि यह आंकड़ा 20 करोड़ लड़कियों का वैश्विक स्तर पर दिखाई देता है, तब यह अचानक से तो नहीं हो सकता है।

भारत में हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के अनुसार, लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, ईसाई विवाह कानून 1872, पारसी धर्म, सिख, बुद्ध, जैन समेत सभी के लिए यही विवाह की उम्र मान्य है, किंतु इस्लाम में शादी के लिए तय की गई उम्र की सीमा इससे अलग है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि किसी लड़की या लड़के में यौवन यानी प्यूबर्टी की शुरुआत हो जाने पर उन्हें विवाह योग्य मान लिया जाता है और यह प्यूबर्टी की उम्र 14 से 15 साल में मानी जाती है । इस्लाम कई इमाम इसे लेकर समझाते हुए मिलते हैं, इनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिन्हें संदर्भ के तौर पर देखा भी जा सकता है। कई तो विवाह की उम्र 14 साल से भी कम बताते हुए मिल जाते हैं।

ऐसे में भारत की कम उम्र में बालिका विवाह की संख्या कौन बढ़ा रहा है, यह स्वभाविक तौर पर समझा जा सकता है । इसका अर्थ यह नहीं है कि हिन्दुओं में विवाह कम उम्र में नहीं हो रहे। ग्रामीण भारत से इस प्रकार की अनेकों शिकायतें मिलती हैं, फिर जिनको संज्ञान में लेकर पुलिस तंत्र समेत कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आकर सुधार के लिए कार्य करती हुई दिखाई भी देती हैं । किंतु क्या यह सुधार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या अनुमानतः जोकि 30 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, उस मुस्लिम जनसंख्या के बीच भी हो रहा है ? यदि नहीं हो रहा है तो फिर छोटी उम्र में विवाह होने का यह आंकड़ा कम नहीं हो सकता है। पिछले साल ऐसे ही एक केस की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हुई । सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले की जांच करने पर सहमति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने के बाद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। किंतु हुआ इसमें वही जो इस्लाम का शरीयत कानून कहता है।

26 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति ने 16 साल की नाबालिग लड़की से शादी की थी और अपनी पत्नी की कस्टडी के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पंजाब पुलिस ने लड़की को इसलिए अपने कब्जे में ले लिया था क्योंकि वह नाबालिग थी। किंतु सब कुछ जानने के बाद उच्च न्यायालय ने लड़की की इच्छा के अनुसार उसकी शादी की अनुमति दे दी, विशेषकर इसलिए क्योंकि मुस्लिम कानून के तहत, लड़की की शादी यौवन प्राप्त करने के बाद भी की जा सकती है। हाई कोर्ट के फैसले में सर दीनशाह फरदुनजी मुल्ला द्वारा विवाह की क्षमता पर लिखे गए मोहम्मडन कानून के सिद्धांतों का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया है; प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क वाला मुसलमान, जो यौवन प्राप्त कर चुका है, विवाह का अनुबंध कर सकता है।पागलों और नाबालिगों, जो यौवन प्राप्त नहीं कर पाए हैं, का उनके संबंधित अभिभावकों द्वारा वैध रूप से विवाह कराया जा सकता है।किसी स्वस्थ मस्तिष्क वाले तथा यौवन प्राप्त कर चुके मुसलमान का विवाह, यदि उसकी सहमति के बिना किया जाता है, अमान्य है। साक्ष्य के अभाव में, पंद्रह वर्ष की आयु पूरी होने पर यौवन की उपधारणा की जाती है।

जब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस मामले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सुप्रीम कोर्ट लेकर गया तो वहां बाल अधिकार निकाय की ओर से तर्क दिया था कि हाई कोर्ट के फैसले ने अनिवार्य रूप से बाल विवाह की अनुमति दी है और यह बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उल्लंघन है। बाल विवाह अधिनियम एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और यह सभी धर्मों पर लागू होगा। एनसीपीसीआर ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 नाबालिगों द्वारा यौन गतिविधि के लिए सहमति को मान्यता नहीं देता है, इसलिए यौवन प्राप्त करने पर विवाह की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इस मुद्दे पर कई उच्च न्यायालयों ने अलग–अलग फैसले भी हैं। जैसे कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीमा बेगम पुत्री खासिमसब बनाम कर्नाटक राज्य (2013) के मामले में कहा था कि "कोई भी भारतीय नागरिक किसी विशेष धर्म से संबंधित होने के आधार पर पीसीएम के आवेदन से छूट का दावा नहीं कर सकता है"। फरवरी 2021 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम जोड़े (17 वर्षीय लड़की और 36 वर्षीय व्यक्ति की शादी) को संरक्षण प्रदान किया, यह मानते हुए कि उनका विवाह व्यक्तिगत कानून के तहत वैध विवाह था। उच्च न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों की जांच की, लेकिन माना कि चूंकि विशेष कानून व्यक्तिगत कानूनों को खत्म नहीं करता है, इसलिए मुस्लिम कानून लागू होगा।

कुल मिलाकर आज इस्लाम एवं कुछ अन्य समाजों में भी बड़ी संख्या में विवाह हो रहे हैं, जबकि बाल विवाह महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। यह बच्चियों से उनके बुनियादी अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार छीनता है, जिसका परिणाम समाज में बलात्कार एवं यौन शोषण समेत अन्य अत्याचारों के रूप में सामने आता है। बाल विवाह के साथ ही किशोर गर्भावस्था एवं चाइल्ड स्टंटिंग, जनसंख्या वृद्धि, बच्चों के खराब लर्निंग आउटकम और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की हानि जैसे परिणाम भी जुड़ जाते हैं। इसलिए सभी इसे रोकने के लिए आज आगे आएं यह बेहद जरूरी हो गया है।

(लेखिका, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं।)

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर महिपाल कांवा को जोधपुर में पकड़ा

35 हजार रुपए का है इनामी : 58 क्विंटल डोडा पोस्त तस्करी में जोधपुर ग्रामीण से 25 हजार व प्रतापगढ़ से 10 हजार का है इनामी

चमकता राजस्थान

जयपुर!(खलील कुरैशी) 02 जुलाई। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने जोधपुर के शताब्दी सर्कल से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त कुख्यात तस्कर महिपाल कांवा पुत्र भागुराम बिश्नोई (32) निवासी सरनाडा थाना डांगियावास जिला जोधपुर को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार तस्कर जोधपुर ग्रामीण पुलिस एवं प्रतापगढ़ पुलिस से 35 हजार रुपए का इनामी है।अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एवं अपराध दिनेश एमएन बताया कि उप महानिरीक्षक पुलिस श्री योगेश यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एजीटीएफ विद्या प्रकाश के सुपरविजन में गठित टीम के सदस्य हैड कांस्टेबल राकेश जाखड़ को सोमवार को मादक पदार्थों की तस्करी में कुख्यात महिपाल बिश्नोई के बारे में सूचना मिली थी।आरोपी तस्कर महिपाल विश्नोई के विरुद्ध वर्ष 2021 में 30 क्विंटल डोडा पोस्त तस्करी के मामले

में प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुर थाने में एवं साल 2023 में जोधपुर ग्रामीण जिले के कापरड़ा थाने में 28 क्विंटल डोडा पोस्त तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों मामलों में आरोपी घटना के समय से फरार था। इसकी गिरफ्तारी के लिए जोधपुर ग्रामीण एसपी द्वारा 25 हजार और प्रतापगढ़ एसपी द्वारा 10 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

एडीजी एमएन ने बताया कि आरोपी तस्कर के बारे में मिली सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष सिंह के नेतृत्व में हैड कांस्टेबल महेश सोमरा, राकेश जाखड़, नरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, महावीर सिंह एवं कांस्टेबल नरेश कुमार व चालक सुरेश कुमार की टीम को रवाना किया गया। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन कर सूचना को विकसित किया।पुष्टि होने के बाद एजीटीएफ द्वारा थाना कापरड़ा जोधपुर ग्रामीण को सूचना दी गई। दोनों टीमो ने संयुक्त कार्रवाई कर जोधपुर शहर में शताब्दी सर्किल के पास से आरोपी तस्कर महिपाल कांवा को देर रात घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपी को डिटेन कर थाना कापरड़ा लाया गया। जिसे पूछताछ के बाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।एजीटीएफ के इंस्पेक्टर सुभाष सिंह तंवर के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्य हैड कांस्टेबल राकेश जाखड़ की इस कार्रवाई में विशेष भूमिका एवं हैड कांस्टेबल महेश सोमरा, नरेंद्र सिंह, रविन्द्र सिंह, महावीर सिंह तथा कांस्टेबल नरेश कुमार व सुरेश कुमार का तकनीकी सहयोग रहा। आरोपी की गिरफ्तारी में एसएचओ कापरड़ा सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल संजय सिंह पांचाराम थोरी व हरसुख चौधरी का सराहनीय योगदान रहा।

संक्षिप्त समाचार

जमीनी विवाद को लेकर दंपत्ति युगल हवाई टंकी पर चढ़े

- दम्पत्ति युगल ने दी आत्महत्या की धमकी

चमकता राजस्थान। वैर (राजवीर सिंह) उपखण्ड की ग्राम पंचायत चक धरसोनी के गांव आजादपुरा के पति पत्नी जमीनी विवाद के न्याय को लेकर पानी की हवाई टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी। ग्रामीणों ने बताया कि रुघन नामक व्यक्ति ने अपनी बहिन की ससुराल में एक प्लॉट खरीदी थी। अपनी पत्नी का जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री भांजे की बहु के नाम करा दी।जानकारी के मुताबिक ये भी बताया कि प्लॉट एक लाख पचास हजार में खरीदी गई। जिसमे पीड़ित ने 50 हजार रुपए देना बताया गया बाकी का एक लाख रुपए उसके भांजे ने देना बताया गया। मामा ने जब पैसे प्लॉट के बकाया पैसा का भुगतान नहीं किया तो भांजे राजा ने प्लॉट को किसी दूसरे के नाम बेचान कर दिया। उसी बात को लेकर मामा माई ने प्लॉट को लेकर हंगामा कर पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय की गुहार लगाने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि एक दो दिन में मामा ने भांजे का पंच पंचायत के फैसले में बकाया पैसा का भुगतान कर दिया बताया गया है। जब पीड़ित को न्याय की उम्मीद नहीं जगी तब आखिरकार पानी की हवाई टंकी पर चढ़कर न्याय की गुहार लगाते हुए आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन के और ग्रामीणों द्वारा काफी समझाइश के बाद दंपत्ति युगल नीचे उतरा।

डॉक्टर्स डे पर डॉ इंदु शर्मा एवं अन्य चिकित्सकों का किया सम्मान

चमकता राजस्थान। भरतपुर (राजवीर सिंह) की डॉक्टर इंदु शर्मा को निदेशालय आयुर्वेद विभाग द्वारा उपनिदेशक का कार्यभार दिए जाने के आदेश के तहत उनके द्वारा कार्य ग्रहण किया गया। डॉ इंदु शर्मा का कौशलेश शर्मा पूर्व जिला अध्यक्ष श्री ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा माला पटका व श्री बिहारी जी की तस्वीर भेंटकर सम्मान किया गया। शर्मा द्वारा डॉ इंदु शर्मा के नेतृत्व में आयुर्वेद विभाग अपनी उल्लेखनीय सेवाओं से आमजन को और अधिक उत्तम सेवाएं प्रदान करने की कामना व्यक्त की। शर्मा द्वारा डॉक्टर्स डे पर डॉ सुशील पाराशर, डॉ राजकुमार शर्मा, डॉ गिरीश कुमार शर्मा का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर समता आंदोलन के अध्यक्ष केदारनाथ पाराशर, अन्नपूर्णा रसोई के प्रभारी विष्णु दत शर्मा, पूर्व विकास अधिकारी राजेंद्र डंडोतिया, बबीता शर्मा, टेक्नोलॉजी पार्क के डायरेक्टर आलोक शर्मा, विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष डॉ सुशील पाराशर, गायत्री परिवार के ट्रस्टी डॉ गिरीश कुमार शर्मा आदि अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

जयपुर विकास प्राधिकरण ने करी प्रभावी कार्रवाई को दिया अंजाम

- जोन-10 में गैर अनुमोदित कालोनी द्वारकापुरी में 12 अवैध विलाजों को किया पूर्णतः ध्वस्त

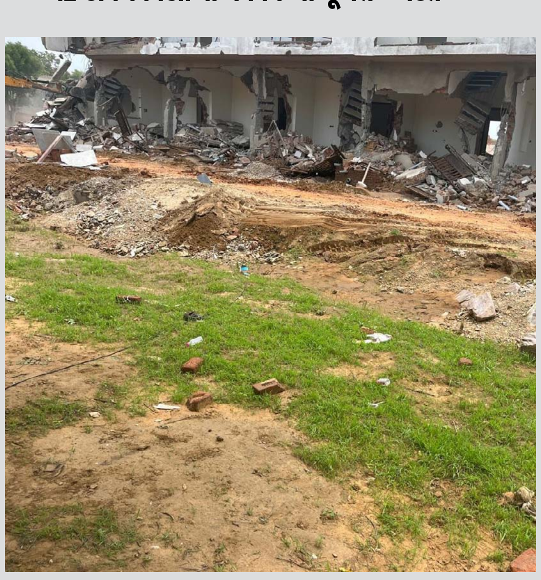

चमकता राजस्थान। जयपुर!(खलील कुरैशी) 02 जुलाई। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन में गैर अनुमोदित योजना द्वारकापुरी में 12 नवीन अवैध विलाजो को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित बाबा बालकनाथ आश्रम के पीछे, जिला जयपुर में गैर अनुमोदित योजना द्वारकापुरी मेंजेडीएकीबिनाअनुमति-स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ वृहद स्तर पर 12 अवैध विलाजों का निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था एवं निर्धारित समय अवधि दी गई थी। निर्धारित समय समाप्त होने के उपरान्त भी निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नही हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आज दिनांकः 02.07.2024 को जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया गया।उक्त कार्यवाहियां उप नियंत्रक-द्वितीय, तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 08, 09, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

कोटा एजीटीएफ व साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई

हज यात्रा व उमराह करवाने के नाम पर 21 लाख की ठगी के आरोपी को उत्तर प्रदेश से किया दस्तयाब

- जिला स्तर पर टॉप टेन में चयनित एवं 25 हजार रुपये का इनामी है आरोपी
- बारां, कोटा व भीलवाडा जिले के पांच मामलों में था वान्टेड

चमकता राजस्थान

जयपुर/कोटा! (खलील कुरैशी) 2 जुलाई। एजीटीएफ कोटा व साइबर सेल पुलिस की टीम ने बड़ी कार्यवाही कर जिले के टॉप 10 में चयनित एवं 25 हजार के इनामी जमरूद्दीन उर्फ मोहम्मद जमरूद्दीन पुत्र निजामुद्दीन (42) निवासी महावीर कॉलोनी नैनवा रोड थाना कोतवाली जिला बूंदी को उत्तर प्रदेश के बरेली से दस्तयाब किया है।एसपी डॉ अमृता दुहन ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध 28 अप्रैल 2019 को महात्मा गांधी कॉलोनी माला फाटक कोटा निवासी अब्दुल फारूक द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उनकी ट्रैवल एजेंसी है जो हज व उमराह पर लोगों को भेजते हैं। हाजियों की देखभाल, उनके यात्रा में भोजन, ठहरने और वापसी तक का पूरा इंतजाम जमीरउद्दीन करता था।साल 2019

की हज यात्रा के लिए उसने 6 जोड़ो के 12 लोगों को हज यात्रा कराने के नाम पर 21 लाख रुपए लिए और गबन कर लिया। रिपोर्ट पर थाना रेलवे कॉलोनी कोटा पर रिपोर्ट दर्ज की गई। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपों को जिला स्तरीय टॉप 10 वांटेड में शुमार कर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया।एसपी डॉ दुहन ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सैनी के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। साइबर सेल व मुखबिरी द्वारा आसूचना संकलन तथा तकनीकी सहायता के आधार पर आरोपी को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार किया गया है।एसपी डॉ दुहन ने बताया कि आरोपी जमरूद्दीन को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया हैम इसके विरुद्ध कोटा शहर जिले के थाना कोतवाली, रेलवे कॉलोनी व थाना मकबरा, बारां जिले के थाना अंता, शाहपुर जिले के थाना जहाजपुर के पांच अपराधिक प्रकरण सहित बूंदी जिले के कोतवाली थाने के एनआई एक्ट के तहत भी आरोपी के विरुद्ध स्थाई वारण्ट जारी है।

जल संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं महासचिव के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन

- ज्ञापन के माध्यम से पहाड़ी बेल्ट में पानी की भयंकर समस्या के निवारण की गयी मुख्य मांग

चमकता राजस्थान। उदयपुरवाटी '(सुमेर सिंह राव)। जल संघर्ष समिति के अध्यक्ष नथू राम व लिगल महासचिव हंसराज कबीर के नेतृत्व में एसडीएम मोनिका सामोर की अनुपस्थिति में उनके रीडर राजेन्द्र कुमार को, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर पीने के पानी के लिए स्थायी समाधान हेतु ज्ञापन दिया है।ज्ञापन में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि उदयपुरवाटी जल संघर्ष समिति लगभग 5 माह से लगातार प्रदर्शन कर रही है कि पहाड़ी बेल्ट में गर्मियों में पीने के पानी की भयंकर किल्लत हो जाती है इसका पीएचईडी प्रशासन और सरकार कोई स्थाई समाधान नहीं निकाल रही है प्रशासन की कोई ठोस रणनीति नहीं है ,केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण परियोजना अमृत 2 फेज में उदयपुरवाटी क्षेत्र को एक रुपया भी नहीं मिला है 'उदयपुरवाटी के पांच गांवों में पहले से कुम्भा राम की लाइन डाली हुई है ,उसके लिए भी अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।उदयपुरवाटी क्षेत्र पहाड़ी बेल्ट होने के नाते यहां पानी की किल्लत बनी रहती है जिसका स्थाई समाधान होना जरूरी है और वह सिर्फ कुम्भाराम पेयजल लिफ्ट योजना के सप्लाई होने पर ही निराकरण हो सकता है। पेयजल टैंकर सप्लाई में ठेकेदार का दुलमुल रवैया टैंकर सप्लाई सिर्फ फाइल में होती रही है।

आगामी बजट 2024 के बजट में उदयपुरवाटी के पहाड़ी क्षेत्र में विशेष रुप से पेयजल के लिए कुम्भाराम पेयजल लिफ्ट योजना,की मंजूरी से ही समाधान हो सकता है। 1994 का यमुना, संशोधित 18 फरवरी 2024 के समझौता पर बजट आवंटित कर प्रेक्टिकल घोषणा की पूरजोर मांग की है।इस अवसर पर नाथूराम जी सैनी, हंसराज कबीर एडवोकेट, सुभाष भाकर, बाबूलाल सैनी किशोरपुरा, शीशराम सैनी मावता, चंदगी राम सैनी दीपपुरा, भगाराम सैनी किशोरपुरा, संदीप कुमार आदि उपस्थित रहे।

साथ ही संघर्ष समिति संयोजक के के सैनी ने एक ब्यान जारी कर, बंद पड़ी पेयजल टैंकर सप्लाई पुनः शुरू करने की पुरज़ोर मांग की है। उन्होंने आगे कहा है कि अभी तक उदयपुरवाटी के 25%क्षेत्र में भी बारिश नहीं हुई है। उदयपुरवाटी के पहाड़ी बैल्ट में हमेशा ही पेयजल की समस्या बनी रहती है,इसके लिए विशेष बजट के लिए सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजने की मांग की है

पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक हुई आयोजित

चमकता राजस्थान

उदयपुरवाटी ' (सुमेर सिंह राव)। ब्लॉक पशुपालन विभाग की समीक्षात्मक बैठक आज ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ कार्यालय उदयपुरवाटी में आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक की समस्त संस्थाओं के प्रभारी अपनी संस्था को आवंटित विभागीय गतिविधियों की लक्ष्यानुसार प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित हुए । पशुपालन विभाग के जिला उपनिदेशक डॉ रणजीत मेहरानिया ने इस दौरान ब्लॉक की समस्त संस्थाओं के भूमि स्वामित्व/भूमि विहीन/ मरम्मत योग्य संस्थाओं

की वस्तुस्थिति, संस्था में नल/ बिजली कनेक्शन/ शौचालय आदि की वस्तुस्थिति, मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट का संचालन, ब्लॉक में संचालित समस्त गौशालाओं की वस्तुस्थिति, संस्था एव कार्मिकों के पद व पदस्थापन संबंधी सूचनाओ तथा टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान व वृक्षारोपण सहित अन्य विभागीय गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा कर ब्लॉक में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी आने जाने, अपनी संस्था के रिकॉर्ड का संधारण एव संस्था भवन की साफसफाई व रख रखाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए साथ ही इस दौरान उपनिदेशक ने ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण भी किया ।इस दौरान बैठक में ब्लॉक उपनिदेशक डॉ मिट्ठू कुमारी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ प्यारेलाल चावला मंडावरा, डॉ सुरेश गहन ककराना, डॉ प्रदीप कुमार पोंख, डॉ नरपत गुढ़ा दहर, डॉ सुरेंद्र सैनी इंदपुरा व पशु चिकित्सा सहायक सुरेश शर्मा, सुरेंदर कुमार, राजेश मील, मोतीलाल गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, विकास कुमार, बनवारी लाल, कल्पना किरोड़ीवाल, बूंटीराम ढाका, राजेश रोहिल्ला, संजू सैनी, प्रियंका कुमारी, राजवीर सिंह, धर्मपाल गुर्जर, सरोज गुर्जर, सरिता रणवा एवं सुमन सहित सभी संस्थाओं के प्रभारी उपस्थित रहे ।

विधानसभा अध्यक्ष ने आहुत करी सर्व दलीय बैठक

नियमों और मर्यादाओं से चलेगा सदनः देवनानी

विधानसभा का सत्र आज से हंगामेदार होने के आसार

चमकता राजस्थान

जयपुर (खलील कुरैशी) राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा इसको लेकर सत्यापन भाजपा और विपक्ष कांग्रेस दोनों ने ही तैयारी कर ली है वहीं इस बार के सत्र में काफी हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष पार्टी कांग्रेस भ्रष्टाचार पेपर ले एक और गहलोत सरकार की योजनाएं बंद करने समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को गर्ने की कोशिश करेगी वहीं सरकार पूरी तरीके से तैयार है जवाबी हम लोग देने के लिए दरअसल इस बार विधानसभा सत्र के अंदर कई बड़े कद्दावर चेहरे नहीं

दिखेंगे जिसमें गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम है मंगलवार को विधान सभा अध्यक्ष ने विधान सभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई। विधान सभा अध्यक्ष की राजस्थान विधान सभा में सदन चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन एक ऐतिहासिक पहल है। विधान सभा अध्यक्ष ने सदन को शांतिपूर्ण चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है।

- **92 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब विधान सभा को प्राप्त हुए**

अध्यक्ष ने बताया कि प्रथम सत्र के 2054 प्रश्नों में से 92 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब विधान सभा को प्राप्त हो गये है। अब 177 प्रश्नों के जवाब आना शेष है। देवनानी ने कहा कि यह शुभ लक्षण है। शेष रहे प्रश्नों के जवाब भी विधान सभा को शीघ्र प्राप्त होने की उम्मीद है। बैठक में तय किया गया कि नया सत्र आरम्भ होने से पहले गत सत्र के सभी प्रश्नों के जवाब विधान सभा को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए।

- **सभी को मिलेगा उचित मौका,शालीनता से मुद्दे उठायें: देवनानी**

सदन में सभी को मिलेगा बोलने का मौका विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी दलों को चर्चा के लिए नियमानुसार समय आवंटित किया जायेगा। समय सीमा में ही सदस्य अधिक से अधिक अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि यह दलों के नेताओं कि जिम्मेदारी होगी कि उनके दल का सदस्य सदन में अपनी बात को आवंटित समय में ही रखने का प्रयास करे। देवनानी ने कहा कि सभी सदस्यगण शालीनता से मुद्दे उठाये।

100 से ज्यादा मोबाईल के बदले ईएमईआई नंबर

जयपुर उत्तर पुलिस ने स्मार्ट फोन के लॉक तोड़कर ईएमईआई नंबर बदलने वाली आपराधिक गैंग को पकड़ा

चमकता राजस्थान

जयपुर। (खलील कुरैशी) राजधानी पुलिस ने स्मार्ट फोन के लॉक तोड़ने के साथ उनके ईएमईआई नंबर को बदलने वाली गैंग को पकड़ा है। पूछताछ में सामने आया कि ये उन फोन के नंबर को क्रेक करते थे, जो ग्राहक किश्त पर लिए फोन लेते थे। शहर की कोतवाली पुलिस ने रायसर प्लाजा में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों की इंद्रा बाजार स्थित रायसर प्लाजा में मोबाइल की दुकान है। इस मामले को लेकर डीसीपी (नॉर्थ) राशि डोगरा डूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। सामने आया कि ये लोग कबाड़ और एक्सचेंज वाले फोन से ये सारा डाटा चुराते थे। इन लोगों ने आसपास ग्रामीण इलाकों में भी अपना नेटवर्क फैला रखा था। 100 से ज्यादा मोबाइल का ईएमईआई नंबर बदला डीसीपी राशि डोगरा ने बताया कि आईटी एक्ट में आरोपी अतुल गुप्ता (36) निवासी सूर्यनगर, गोपालपुरा, महेश नगर, लोकेश गर्ग उर्फ लालू (30) निवासी महावीर कॉलोनी विस्तार, करतारपुरा, महेश नगर हाल मांग्यावास मानसरोवर, गौतम सैनी उर्फ गोलू (38) निवासी रविन्द्र नगर, जगतपुरा, प्रतापनगर और महेश मुरजानी (53) निवासी सेक्टर-16, प्रताप नगर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कोतवाली थाना पुलिस को 30 जून की शाम सूचना मिली कि रायसर प्लाजा में कुछ दुकानदार मोबाइल लॉक-अनलॉक करने और ईएमईआई नंबर क्रेक करने का काम कर रहते है। कोतवाली थाना पुलिस ने डीएसटी नॉर्थ के साथ मिलकर रायसर प्लाजा में छापेमारी की।

250 से अधिक मोबाइल और अन्य उपकरण जब्त

» पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कम्प्यूटर, डेस्कटाप, लॉक तोड़ने और ईएमईआई नंबर क्रेक करने का सॉफ्टवेयर डिवाइस और 250 से ज्यादा मोबाइल जब्त किए है। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से करीब 100 से अधिक बदले गए मोबाइल के ईएमईआई नंबर का रिकॉर्ड ट्रेस आउट भी जयपुर ग्रामीण में भी थे इनके ग्राहक मिले हैं।

किश्त पर लिए फोन का ईएमईआई नंबर बदल कर आपराधिक घटनाक्रम को अंजाम

» पुलिस ने चारों आरोपियों की दुकान से बड़ी संख्या में पुराने मोबाइल भी बरामद किए है। इनके पास एक रजिस्टर भी मिला है। इसमें 100 ईएमईआई नंबर की डिटेल है, जिन्हें दूसरे मोबाइल के लॉक तोड़ अपडेट किया गया है। इसके अलावा ये लोग खराब हो चुके की–पेड और स्मार्ट फोन भी अपने पास रखते थे। आरोपियों ने जयपुर और जयपुर ग्रामीण में भी अपने कस्टमर बना रखे थे।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जो ग्राहक किश्त पर फोन लेते है और समय पर वे उसे चुका नहीं पाते हैं तो उनका फोन लॉक हो जाता है। ऐसे में ये लोग कम्प्यूटर सिस्टम से मोबाइल का लॉक तोड़ देते थे और फिर ईएमईआई नंबर बदल देते थे। इनके पास कम्प्यूटर सिस्टम में (UMT TOOL, MTK-2, NEW AMT, UNLOCK TOOL-2, BORNIO, ZWX) सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था। जबकि 20–25 हजार रुपए कीमत का हार्डवेयर डिवाइस (हार्डवेयर टूल ऋह, वऋक, एअर खळअऋ) का यूज करते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जरिए ये पूरा काम होता था। आरोपियों ने बताया कि जिस मोबाइल का ईएमईआई नंबर बदलना होता उसे पहले कम्प्यूटर से कनेक्ट करते थे। कम्प्यूटर से कनेक्ट करने के बाद इन सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे फोन को रिस्टोर कर देते थे। इसके बाद जब इसमें मोबाइल की डिटेल मांगी जाती तो मॉडल नंबर और दूसरी जानकारी तो उसी फोन की रखते थे। लेकिन, जब ईएमईआई नंबर सॉफ्टवेयर मांगता तो ये किसी पुराने कबाड़ हुए या फिर एक्सचेंट में आए फोन के नंबर डालकर उसे अपडेट कर देते थे।

संक्षिप्त समाचार

प्रवीण गुप्ता की मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद से विधिवत रूप से हुई भव्य विदाई

● नवीन महाजन के संभाला राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार

चमकता राजस्थान। जयपुर। (खलील कुरैशी) राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी पदस्थापन आदेश के बाद प्रमुख शासन सचिव प्रवीण गुप्ता को निर्वाचन विभाग की ओर से राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद से विदाई दी गई। गुप्ता अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव के पद पर सेवाएं देंगे। इससे पूर्व मंगलवार को ही प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रवीण गुप्ता को सचिवालय के कांफ्रेंस सभागार में निर्वाचन विभाग के सभी अधिकारियों और कार्मिकों ने एक सादे समारोह में भावभीनी विदाई दी. इस दौरान गुप्ता ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य को न्यूनतम संसाधनों के बावजूद अधिकतम उत्कृष्टता के साथ पूरा करने के लिए बधाई दी और आभार जताया. उन्होंने कहा कि आप लोगों के अथक प्रयासों और मेहनत के परिणामस्वरूप गत लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान राजस्थान के निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हुए कई सफलताएं अर्जित की और देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नए मापदंड स्थापित किए हैं.निर्वाचन विभाग के अधिकरियों ने गुप्ता के साथ बिताए चार वर्षों के कार्यकाल के अनुभव साझा किए और उनकी उल्लेखनीय कार्यनीति और काम के प्रति जूनून की प्रशंसा की. विभाग के विशेषाधिकारी श्री सुरेश चन्द्र ने विभाग के सभी कार्मिकों की ओर से आश्वासन दिया कि गुप्ता के नेतृत्व में विभाग में अटूट समर्पण, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता से जो उच्च मानक स्थापित हुए हैं, वे आगे भी जारी रहेंगे।

दौसा जिले में थाना महवा पुलिस की कार्रवाई

टॉप 10 में शुमार 3 अभियुक्तों सहित पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

● इनमें 5 साल से फरार दो गौतस्कर, एससी/एसटी एक्ट प्रकरण व छेड़छाड़ के दो आरोपी एवं एक सन्दिग्ध बाइक सवार है

चमकता राजस्थान। जयपुर/दौसा (खलील कुरैशी) 02 जुलाई। दौसा जिले की महवा थाना पुलिस की टीम ने सोमवार को टॉप 10 में शुमार तीन अभियुक्तों सहित कुल 5 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो 5 साल से फरार गौ तस्कर, एससी/एसटी एक्ट प्रकरण एवं छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपी एवं एक सन्दिग्ध बाइक सवार शामिल है एसपी रंजीता शर्मा ने बताया कि अनिल कुमार टांक के निर्देश पर टॉप 10, इनामी गिरफ्तारी वा-रंट एवं अन्य वांछित

अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश अग्रवाल व सीओ राजेंद्र कुमार के सुपरविजन एवं एसएचओ महवा जितेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में सोमवार को इन पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।एसपी शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान थाना पुलिस द्वारा माली मोहल्ला महवा निवासी ओमप्रकाश सैनी पुत्र मुकेश (22) के पास एक संदिग्ध एफजेड बाइक पाए जाने पर धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर एमवी एक्ट में बाइक जप्त की गई। इसी प्रकार 5 साल से फरार टॉप 10 में शामिल दो गौतस्कर इकलास उर्फ काडा पुत्र जुहरु उर्फ नूरु उर्फ नूर मोहम्मद मेव (27) व समीन उर्फ टांका पुत्र आसीन मेव (34) निवासी घाटमिका थाना पह-ाड़ी जिला डीग को गिरफ्तार किया गयाइसी प्रकार एससी/एसटी एक्ट व छेड़छाड़ के प्रकरण में आरोपी श्याम जोगी पुत्र नंगू राम (30) एवं एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण में अन्य आरोपी योगेश योगी पुत्र महेंद्र (20) निवासी शहदपुर थाना महवा को गिरफ्तार किया गया।

भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल की हुई महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक : गहलोत सरकार का एक और फैसला पलटा

किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में खुलेंगे फ्लाइंग स्कूल

चमकता राजस्थान

कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और जयपुर में बनेगी एयरोसिटी

जयपुर (खलील कुरैशी)भजनलाल सरकार की साढ़े तीन महीने बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। गहलोत सरकार में बनाए गए गांधी वाटिका न्यास को भंग कर दिया गया है। हालांकि गांधी वाटिका का संचालन होता रहेगा। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसे लेकर अगस्त में एमओयी होगा। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र बैरवा ने बताया कि दानदाताओं को सम्मानित करने एवं प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से चूरू जिले के राजकीय महाविद्यालय, साहवा का नामकरण श्रीमती मोहनी देवी चाचान राजकीय महाविद्यालय, साहवा, बाड़मेर जिले के राजकीय महाविद्यालय, धोरीमन्ना का नामकरण शांति देवी उदयराज गांधी राजकीय महाविद्यालय, धौरीमत्रा एवं बीकानेर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीडूंगरगढ़ का नामकरण राजकीय सदू देवी पारख कन्या महाविद्यालय, श्रीडूंगरगढ़ करने की मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 एवं राजस्थान भू- राजस्व (अक्षय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयत्रों की स्थापना हेतु राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के प्रावधानों में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केन्द्रित है। इसके अंतर्गत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जयपुर में एयरोसिटी बनाई जाएगी जिसमें होटल, रेस्त्रां सहित विभिक्षा आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम-2023 को समाप्त करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023 में लाए गए अधिनियम की विभिन धार-ाओं में उपाध्यक्ष को असीमित वित्तीय शक्तियां दी गई थी। व्यास से संबंधित किसी भी प्रकार की स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, बंधक या निपटान करने का अधिकार उपाध्यक्ष को दिया गया था।

होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान मोटा अनाज (millets) प्रमोशन एवं शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ संयुक्त रूप से करेगा काम

चमकता राजस्थान

जयपुर (खलील कुरैशी) होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान का प्रतिनिधि मंडल खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक विभाग राजस्थान सरकार केअधिकारियों के साथ बैठक कर अनेक विषयों पर चर्चा की इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्तइकबालखान(वरिष्ठ आई.ए.एस.), निदेशक पंकज ओझा, संयुक्त निदेशक एसएन धौलपुरिया के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे मोटा अनाज प्रमोशन के लिए होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा चलाए गए अभियान पर निदेशक पंकज ओझा ने फेडरेशन का धन्यवाद एवं आभार जताया. इस अवसर पर ओझा ने कहा की होटल फेडरेशन आफ राजस्थान विभाग द्वारा चलाए जा रहे खाद्य सुरक्षा (शुद्धिकरण) अभियान में सहयोग करें एवं आगामी दिनों में कार्यशाला आयोजित कर पर्यटन सेक्टर से जुड़े हुए व्यवसाईयों एवं आमजन को जागृत करने के लिए विभाग का सहयोग करें. फेडरेशन के अध्यक्ष हुसैन खान ने पंकज ओझा को आस्वस्थ किया की मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मोटे अनाज के प्रमोशन के लिए चलाए जा रहे अभियान के साथ-साथ हम खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए गए अभियान में भी निश्चित रूप से सहयोग करेंगे.होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान आगामी दिनों में पर्यटन सेक्टर सै जुड़े व्यवसाईयों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के सहयोग से कार्यशाला का आयोजित जल्द करेगा पंकज ओझा ने होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए जारी किए गए पोस्टर को विभाग के सभी ऑफिस में लगाने के निर्देश दिए खाद्य विभाग राजस्थान आयुक्त इकबाल खान ने भी फेडरेशन द्वारा सक्रिय रखकर आमजन के हित के विभिन्न आयोजन करने पर तारीफ की. एवं आगामी दिनों में विभाग के सहयोग का भी आश्वासन दिया मोटा अनाज के बने व्यंजनों में में शरीर के लिए आवश्यक फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम,जिंक, कैल्शियम, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके साथ-साथ मोटा अनाज ब्लड प्रेशर, शुगर एवं कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी सहायक होते हैं !मोटा अनाज बाजार, जवार,जौ, मक्का, राजगीर सांनवा, कुट्टू, रागी, कागनी, कोड़ों सामा, चना विशेष रूप से प्रचलित हैं मोटा अनाज (मिलेट्स) राजस्थान में प्रचुर मात्रा मैं उत्पादन होता है. अन्य अनाजों से सस्ता भी मिलता है. देखा गया है कि जनता में जागृति के बाद हेल्दी डाइट में शुमार मिलेट्स अब लोगों की डाइट में भी शामिल होने लगा है. जो आगामी दिनों में लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत है.

● यें गणमान्य रहे मौजूद

खाद्य सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक के अवसर पर होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान,वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह,सचिव शैलेश प्रधान, सदस्य, संजय खंडेलवाल, भंवर यादव, पीयूष, अश्वनी ठकराल,विपुल मैंनी,सीताराम शर्मा व अन्य उपस्थित रहे.

दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुए जनसेवा के कार्यक्रम

● सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का हुआ आयोजन

● कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं एवं आमजन को गर्मी से राहत देने के तीन वाटर कुलर की गयी स्थापना, हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम

चमकता राजस्थान। जयपुर (खलील कुरैशी)। दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेटस बार एसोसियेशन जयपुर अध्यक्ष गजराज सिंह राजावत ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में 3 वारट कूलर का उद्घाटन व भामाशाहो का सम्मान समारोह व वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके मुख्य अतिथि सिविल लाईन विधान सभा के विधायक गोपाल शर्मा थे कार्यक्रम की अध्यक्षता ए.डी.एम प्रथम सुरेश नवल ने की, मुख्य अतिथि गोपाल शर्मा ने पार्किंग की समस्याओ के लिये घोषणा की कि शीघ्र ही कलेक्ट्री सर्किल पर पार्किंग का निर्माण करवाया जायेगा। दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेटस बार एसोसियेशन जयपुर व दी बार एसोसियेशन जयपुर के अधिवक्ताओ व आम जनता के बैठने के लिये एडवोकेट दीर्घा के निर्माण के लिये 25-25 लाख रूपये की राशि विधायक कोष से अलग अलग दी जाने की घोषणा की। महासचिव अखिलेश जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में जयपुर बार एसोसियेशन के अध्यक्ष पवन शर्मा व महासचिव राजकुमार शर्मा दिनेश कुमावत एडवोकेट व दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेटस बार एसोसियेशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष विवेक शर्मा वृक्षारोपण कार्यक्रम के संयोजक अविनाश गोड व दीपक शर्मा भामाशाह रेखा पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा, रजनीश गोड, राकेश शर्मा श्याम सिंह राठौङ, गोपाल कृष्ण नारोलीया राजेश मीणा रमेश कुमार, सीताराम सैनी ,रोशन लाल शर्मा, प्रदीप सिंह,दीपक सिंह जोधा,शत्रुघ्न सिंह,रमेश सिंह, सीताराम कुमावत प्रेम कुमार शर्मा,धमेन्द्र निर्वाण रेवती रमण आदि मौजुद रहे।

एक नजर

आईईएम-यूईएम ने फ्रेशर्स का स्वागत करने के लिए रोबोट डॉग का अनावरण किया

कोलकाता। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (आईईएम) और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कोलकाता (यूईएम) के छात्रों ने आईईएमए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के शोधकताओं के सहयोग से एक उन्नत रोबोट डॉग का अनावरण कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आईईएम-यूईएम परिसर में प्रथम वर्ष के छात्रों के नए बैच के उद्घाटन समारोह के दौरान, इस तकनीकी नवाचार ने उनका स्वागत भी किया। मुख्य रूप से, रोबोट डॉग परियोजना नए छात्रों का स्वागत करने के लिए थी,प्रो. अमर्त्य मुखर्जी, प्रो. अयान कुमार पांजा और सौविक चटर्जी द्वारा निर्देशित आईईएमए की इस टीम ने रोबोटिक्स और एआई में एक नया मानदंड स्थापित किया। आईईएम-यूईएम ग्रुप के निदेशक प्रोफेसर डॉ. सत्यजीत चक्रवर्ती ने कहा कि रोबोट डॉग जैसी परियोजनाएं संस्थान में छात्रों और शिक्षकों की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं।

सवारी गाड़ी की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

अररिया। फारबिसगंज -बथनाहा -जोगबनी रेलखंड में भद्रेश्वर नहर के समीप सोमवार की देर रात जोगबनी से कटिहार जाने वाली यात्री गाड़ी संख्या 07546 के चपेट में आने से एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के कारण करीब एक घंटे तक ट्रैक पर ट्रेन खड़ी रही।बाद में रेल पुलिस और बथनाहा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए ट्रैक पर से शव को हटाया।जिसके बाद रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो पाया।मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।रेल पुलिस स्थानीय लोगों के मदद से शव के शिनाख्त में जुटी है।मामले को लेकर बथनाहा थानाध्यक्ष धनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि मामला रेल पुलिस का है और प्रथम दृष्टया शव को देखने पर ऐसा लगता है।

पूर्व विधायक एव समाजसेवी अनुसूइया जायसवाल का निधन

सीवान। महाराजगंज की पूर्व विधायक एवम समाजसेवी अनुसूइया जायसवाल का निधन दिल्ली में हो गया। वे काफी वयोवृद्ध हो चुकी थी। स्व० जायसवाल ने महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से सन 1957 एव 1972 में कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीती थी। वे डॉ० जगन्नाथ मिश्रा के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार राज्य वेयर हाउसिंग बोर्ड की चैयरमैन भी रह चुकी थी। वे लगातार हीं राजनीति एवं समाजसेवा में सक्रिय रही। उनके निधन से महाराजगंज ने अपना एक लोकप्रिय नेता खो दिया है। उनके निधन पर शोक व्यक्त करने वालो में वरिष्ठ पत्रकार एव समाजसेवी ई०प्रमोद रंजन, नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि शक्ति शरण प्रसाद, नगर पंचायत उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि पवन कुमार, राजद नेता राजकिशोर गुप्ता, हरिशंकर प्रसाद आशीष, समाजसेवी मनोज त्यागी, पूर्व नगर पार्षद सत्येंद्र कुमार छोटे, राजद नेता चंदन कुमार गुड्डू, वार्ड 3 केनगर पार्षद के प्रतिनिधि सुमन सेनानी, अनीश कुमार गोला, अभिषेक कुमार कान्हा, राजन कुमार, हिंदी दैनिक झारखंड दर्शन के प्रबंध संपादक विनय कुमार तिवारी शामिल हैं।

महिला की गोली मारकर हत्या

नवादा । नवादा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उड़ीसा गांव के समीप मंगलवार को अज्ञात कार सवार बदमाशों ने एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक महिला की पहचान वारसलीगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी स्वर्गीय विवेकानंद सिंह की पत्नी ममता देवी के रूप में किया गया है। मृतका के भैसुर राजेश कुमार ने बताया कि अपने बाइक से अपने घर दौलतपुर जा रहे थे ।तभी उड़सा गांव के समीप अज्ञात कार पर सवार बदमाशों ने रोकने का इशारा किया। इसके बाद अपराधियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। जिससे महिला को गोली लग गई। जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं वर्ष 2018 में भी जमीन विवाद में उनके पति की गोली मारकर हत्या की गई थी। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

राज्यसभा भेजे जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, बनी सहमति

पटना। एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। एनडीए ने यह फैसला सभी सहयोगी दलों की सहमति से लिया है, जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का निर्णय एनडीए के सभी दलों का सामूहिक फैसला है। यह कदम कुशवाहा समुदाय के समर्थन को बनाए रखने के लिए उठाया गया है, जो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटक है। उल्लेखनीय है कि उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव में हार का सामना किया था। इसके बावजूद बिहार में कुशवाहा वोट बैंक की महत्वपूर्णता को देखते हुए एनडीए ने उन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है।

ईडी की पूछताछ में रितुपर्णा ने 70 लाख रुपये लौटाने की इच्छा जताई

एजेंसी

कोलकाता। राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में ईडी की पूछताछ के बाद अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता ने 70 लाख रुपये लौटाने की इच्छा जताई है। यह दावा मंगलवार को ईडी सूत्रों ने किया है। रितुपर्णा पिछले जून में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय गई थीं। पांच घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। अभिनेत्री ने तब मीडिया के सामने दावा किया कि राशन भ्रष्टाचार से उनका कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, उनसे जो दस्तावेज मांगे गए थे, उन्होंने जांचकताओं को सौंप दिए है। ईडी के एक अधिकारी ने दावा किया कि जांचकताओं ने राशन भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार एक आरोपित के साथ रितुपर्णा के वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उस सूत्र के माध्यम से यह भी पता चला है कि आरोपित के साथ एक कंपनी का करोड़ों रुपये का वित्तीय लेनदेन हुआ है, जिसकी मालकिन के रूप में अभिनेत्री रितुपर्णा का नाम है। लेन-देन के बारे में जानने के लिए ईडी ने रितुपर्णा को तलब किया था। हालांकि, रितुपर्णा 19 जून को ईडी कार्यालय गईं। करीब पांच घंटे बाद एक्ट्रेस ईडी दफ्तर से बाहर आईं। कार में बैठने से पहले रितुपर्णा ने कहा, "जांचकर्ता मेरे सहयोग से खुश हैं। मेरा इस भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने (जांचकताओं ने) भी सहयोग किया, मैंने भी सहयोग किया।" इससे पहले जुलाई 2019 में रितुपर्णा और अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी से रोज वैली मामले की जांच कर रही ईडी ने पूछताछ की थी। एक समय में रोज वैली कंपनी द्वारा कई बांग्ला फि ल्मों का निर्माण किया जाता था। उस समय ईडी की ओर से बताया गया था कि रितुपर्णा से संस्था के प्रमुख गौतम कुंडू ने संपर्क किया था। रोजवैली समूह ने बाद में टॉलीवुड अभिनेत्री की एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रितुपर्णा ने गौतम कुंडू की कंपनी द्वारा निर्मित कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया। पांच साल पहले ईडी ने उन्हें साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बुलाया था और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी जुटाई थी।

चोपड़ा नहीं गए, राज्यपाल सिलीगुड़ी से दिल्ली लौट गए

संवाददाता

कोलकाता। हालांकि चोपड़ा के पास जाने की योजना थी, लेकिन अंत में राज्यपाल नहीं गये। सूत्र की खबर कुछ ऐसी है। चोपड़ा मामले को लेकर राज्य में उबाल है, सिर्फ चोपड़ा ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कई जगहों पर मार-पीटकर हत्या की घटनाएं हुई हैं। सीवी आनंद बोस चोपड़ा के पीड़ितों से मिलने के लिए दिल्ली से सिलीगुड़ी आए। बागडोगरा से सड़क मार्ग से उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा जाने की योजना थी। दुर्व्यवहार करने वाले जोड़े से बात करना था। चोपड़ा पहुंचने से पहले उन्होंने सिलीगुड़ी में पत्रकारों को संबोधित किया। चोपड़ा की आपबीती उन्हीं की जुबानी। राज्यपाल ने कहा, भारत में महिलाओं को भगवान के रूप में पूजा जाता है। लेकिन बंगाल में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। इसके बाद राज्यपाल ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, 'राज्य सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से मैं देख रहा हूं कि सरकार इसका समर्थन कर रही है।' इस राज्य में सरकार समर्थित हिंसा चल रही है। यह मामला बेहद चिंता का विषय है।' सूत्रों के मुताबिक, आखिर में वह चोपड़ा के पास नहीं गए। चोपड़ा ने अचानक अपना दौरा रद्द कर दिया और सिलीगुड़ी से दिल्ली लौट गए।

ऊंची ब्याज दरों के कारण दासपुर के सैकड़ों ग्रामीणों को लाखों रुपये का हुआ नुकसान

संवाददाता

कोलकाता। अगर आप एक लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको हर महीने आठ हजार रुपये वापस मिलेंगे! दासपुर के बेनई गांव के करीब दो सौ ग्रामीण ऐसी धोखाधड़ी के जाल में फंस गये। सोमवार को ठगे गए लोगों ने दासपुर थाने में शिकायत दर्ज कराकर रकम वापस दिलाने और जालसाज को सजा देने की मांग की। दासपुर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि दासपुर ब्लॉक नंबर दो के बेनई गांव के दंपती हरू पाल और तनुश्री पाल ने इस जालसाजी में फंसाने के लिए करीब दो करोड़ रुपये का गबन किया।

पता चला है कि बेनई गांव के दंपति ने पड़ोसी महिलाओं को बताया कि वे एक बड़ी कंपनी के निदेशक हैं। अगर आप उस कंपनी में एक लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको हर महीने आठ हजार रुपये वापस मिलेंगे। कई लोग गांव के परिचित लोगों पर भरोसा कर बड़ी रकम जमा कर रहे थे। कई लोग लालच संभाल नहीं पाए और बैंक से लोन लेकर पैसे थमा दिए। चार माह तक हर माह आठ हजार रुपये बैंक खाते में जमा होते रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान लक्ष्य टाई हो गया था। स्थानीय निवासी सुकांता रोंग ने कहा, "हममें से किसी को उन पर शक नहीं हुआ क्योंकि वे गांव के निवासी थे। मैंने वादे के मुताबिक बिना जमा रसीद के पैसे दे दिए हैं। पिछले पांच माह से पैसा जमा नहीं होने के कारण हमें संदेह हुआ। वे दोनों पैसे वापस मांगने के लिए घर की चाबियाँ लेकर निकल पड़े। कहा जाता है कि सुकांत बाबू जैसे गांव के लगभग दो सौ निवासी इस धोखाधड़ी चक्र के जाल में फंस गए हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं हैं। महिलाओं ने किसी से एक लाख तो किसी से दो लाख टका लेने का दावा किया।

पता चला है कि दम्पति एसडीएफएक्स ग्लोबल नाम की फर्जी कंपनी के नाम पर पैसे निकालते थे। बेनई गांव निवासी शीला पात्रा ने एक लाख 90 हजार रुपये जमा किये। राखी हाइती ने 60 हजार रुपये जमा किये। उन्होंने कहा, "हमने वह पैसा उधार लेकर जुटाया। पहला पैसा जमा हुआ। जिसे देखकर कई लोग आगे आये। पिछले पांच माह से पैसा जमा नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप, हम ऋण राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। हमने बार-बार पूछा तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया। अचानक मैंने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। दोनों ही लापरवाह हो गए हैं।

शिक्षा मंत्री से मिलकर विधायक विजय खेमका ने रखी समस्या

पूर्णिया। सदर विधायक विजय खेमका ने पूर्णिया विधानसभा अंतर्गत दर्जनों प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन, चाहरदिवारी, शौचालय, पेयजल की सुविधा नहीं रहने से छात्र छात्राओं को हो रही कठिनाई से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मिलकर अवगत कराया । इस वर्ष के लिए जिन विद्यालयों में आवश्यकतानुरूप आधारभुत सुविधाओं की अति आवश्यकता है उन विद्यालयों की सूचि माननीय मंत्री जी को दिया` विधायक ने नगर निगम अंतर्गत मध्य विद्यालय उफरैल को उत्क्रमित करने का मंत्री जी से आग्रह किया ताकि घनी आबादी वाला वार्ड 10, 11, 12 एवं 24 के छात्र छात्राओं और अभिभावकों की कठिनाई दूर हो सके` विद्यालय विकास के लिए गठित प्रबंध समिति के अधिकार को शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा सिमित करने की जानकारी विधायक ने माननीय मंत्री को दी।

पुलिस के खिलाफ अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की

संवाददाता

कोलकाता। नेशनल मेडिकल कॉलेज में सिविक वॉलंटियर्स ने मरीज के परिजनों को बेरहमी से पीटा। इस घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन ने पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। इसमें डीन, नर्सिंग अधीक्षक समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन इस बात पर संदेह है कि क्या पुलिस जांच कर पाएगी क्योंकि घटना अस्पताल के अंदर हुई थी। पता चला है कि अस्पताल इस संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों पर गौर करना चाहता है। अस्पताल परिसर में एक मरीज के परिजन की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल होते ही हंगामा शुरू हो गया। मरीज के परिजनों की शिकायत है कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ना पड़ता है। इसी बीच आपातकालीन कक्ष में इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की तबीयत बिगड़ गयी। आरोप है कि जब परिजनों ने मदद मांगी तो पुलिस और सिविक वॉलंटियर्स ने पलटकर उनकी पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में मरीज के परिजनों को लाठी-डंडों से जमकर पीटते देखा जा रहा है। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। महिलाओं की परवरिश बिना महिला पुलिस के होती है। पता चला है कि मरीज कोलकाता का रहने वाला है। घटना के बाद परिजन मरीज को अस्पताल से घर ले गये। हालांकि, बताया गया है कि घटना की कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है।

महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में ए.सी.बी. भ्रष्टाचारीयों के खिलाफ दे रही है निर्बाध रूप से कानूनी कारवाई को अंजाम

अलवर में पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ का हैड कानिस्टेबल एवं उसका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

चमकता राजस्थान

जयपुर!(खलील कुरैशी) 02 जुलाई, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. अलवर-प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मुरारीलाल मीणा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर एवं उसके दलाल मंगल खाँ मेव (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर-प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि उसके एवं उसके परिजनों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में आरोपियों के नाम निकालने की एवज में मुरारीलाल मीणा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा उसके दलाल मंगल खाँ मेव (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 1 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।जिस पर एसीबी जयपुर केउपमहानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरवीजन में ए.सी.बी. अलवर-प्रथम इकाई के उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण मुरारीलाल मीणा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर एवं उसके दलाल मंगल खाँ मेव (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वा-रा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं हैं३रंस्त्रस्र हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 247 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।

कोटा और जयपुर हैरिटेज नगर निगम में जमीन का अवैध बेचान करने का आरोप यूडीएच मंत्री से मिले हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों ने की पट्टा और ऑक्शन निरस्त करने की मांग

चमकता राजस्थान

जयपुर।(खलील कुरैशी) राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर बोर्ड की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने से रोकने की मांग की। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष दशरथ कुमार के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने बताया कि नगर निगम कोटा और नगर निगम हैरिटेज जयपुर में हाउसिंग बोर्ड की करोड़ों रुपए कीमत की बेशकीमती जमीन थी, उसे बेच दिया है। दशरथ कुमार ने ज्ञापन देकर बताया कि पिछली सरकार में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान कोटा के महावीर नगर थर्ड के सेक्टर-7 स्थित 1175 वर्गगज जमीन का पट्टा नगर निगम कोटा दक्षिण ने आनन-फानन में जारी कर दिया, जबकि इस जमीन का मालिकाना हक हाउसिंग बोर्ड का है। इसी तरह नगर निगम हैरिटेज जयपुर ने भी पिछले महीने 13 जून को जयपुर के जवाहर नगर स्थित 1600 वर्गगज जमीन का ऑक्शन कर दिया। ये जमीन रिकॉर्ड में हाउसिंग बोर्ड की है और बोर्ड प्रशासन का इस पर मालिकाना हक है।

हाउसिंग बोर्ड को हुआ व्यापक स्तर पर भारी नुकसान

» संघ के प्रदेश महामंत्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि पिछली सरकार में मंडल की कई बेशकीमती जमीनों को आनन–फानन में सरकार ने ऑक्शन करके खुर्द–बुर्द कर दिया। इससे बोर्ड प्रशासन को बहुत अधिक राजस्व का नुकसान हुआ है। महामंत्री ने मंत्री खर्रा से कोटा नगर निगम की ओर से जारी पट्टे को निरस्त करने और नगर निगम हेरिटेज की ओर से किए गए ऑक्शन को निरस्त करने की मांग की है।

एक नजर

केन्या में नए कर कानून के खिलाफ नागरिक सड़कों पर, 39 की मौत

नैरोबी। केन्या में नए कर कानून के खिलाफ हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में कम से कम 39 लोग मारे गए हैं। स्थानीय समाचार पत्र पीपल डेली की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार और सुरक्षा एजेसिंयों की चेतावनी का नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। नागरिक नए सिरे से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं। केन्या नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के के मुताबिक केन्या में कर कानून के विरोध हुए देशव्यापी प्रदर्शनों में 39 लोग मारे गए हैं और 361 घायल हुए हैं। इसके अलावा 32 लोग लापता हैं। इस दौरान 627 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर, बिगड़ती कानून व्यवस्था से चिंतित केन्या के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षाबलों को तैनात करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि केन्या में मई में फाइनेंस विधेयक 2024 पेश किया गया था। रोजमर्रा के उपयोग की चीजों पर भारी-भरकम टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को लेकर संसद में वोटिंग हुई। करीब 195 सांसदों में से 106 ने इसके पक्ष में वोट किया। इसकी भनक लगते ही सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया।

अखाड़े पैसा कमाने और भण्डारे खाने वाली कम्पनी बनेः आनंद स्वरूप

हरिद्वार। शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि अखाड़ों का निर्माण हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। अखाड़ों के संतों ने बाबर, अकबर और औरंगजेब आदि अनेक मुगल आंक्रांताओं के साथ युद्ध लड़कर हिन्दू धर्म की रक्षा की। आज अखाड़े के संत का काम केवल भण्डारे खाना और वहां दक्षिणा कितनी मिलेगी यही रह गया है। स्वामी आनंद ने कहा कि अखाड़ों की छावनियों में प्रशिक्षण बंद कर दिए गए हैं। अखाड़े आज पैसा कमाने की कम्पनी मात्र बनकर रह गए हैं। अखाड़ों ने अपना काम बंद कर दिया है। अखाड़े के केवल कुंभ में छावनियां लगाने तक सिमट गए हैं। उन्होंने अखाड़ों के संतों ने उठ खड़े होने व हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

दो युवक अफीम के साथ गिरफ्तार

फतेहाबाद। नशा तस्करों की धरपकड़ करते हुए फतेहाबाद पुलिस की टीम ने गांव काजलहेड़ी के दो युवकों को भारी मात्रा में अफीम सहित गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम एएसआई जसबीर सिंह के नेतृत्व में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने को लेकर गश्त पर थी। टीम जब रतिया चुंगी, हांसपुर रोड फतेहाबाद पर पहुंची तो उन्हें सूचना मिली कि कुलदीप सिंह व अजय निवासी काजलहेड़ी देनें युवक अफीम तस्करी का धंधा करते हैं। आज भी वह अपनी कार में अफीम लेकर स्वामी ढाबे के आगे हांसपुर रोड की तरफ कार में बैठकर ग्राहक का इंतजार कर रहे है।

घर से मोबाइल चुराकर खाते से एक लाख रुपये निकाले, केस दर्ज

फतेहाबाद। घर से मोबाइल फोन चुराकर एक चिनाई मिस्त्री के खाते से एक लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। इस बारे पीड़ित युवक ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दी जिसके बाद मंगलवार को फतेहाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस बारे पुलिस को दी शिकायत में गांव हिजरावां खुर्द निवासी रमेश सिंह ने कहा है कि वह चिनाई मिस्त्री का काम करता है। कुछ दिन पूर्व अज्ञात व्यक्ति उसके घर से उसका मोबाइल फोन उठाकर ले गया। उसका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और उसमें यही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। उसके मोबाइल फोन में ही उसके सभी कागजात के फोटो भी थे। उसने आरोप लगाया कि अज्ञात ठग ने उसके मोबाइल फोन में से छेडखानी करते हुए ओटीपी का पता लगाकर उसके बैंक खाते से एक लाख रुपये ट्रांजेक्शन करके हड़प लिए है।

जमीन के विवाद में दो में पक्षों खूनी संघर्ष

हरिद्वार। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बहादरपुर खादर गांव के बस स्टैंड के पास सोमवार की देर रात जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे व धारदार हथियार चले, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बहादुरपुर खादर गांव के अड्डे पर अमरीश कश्यप व अशोक सैनी और उसके परिवार की जमीन है। अमित कश्यप अपनी जमीन में दुकान का निर्माण कर रहा था, जबकि अशोक के परिवार के लोग निर्माणधीन जमीन को अपना बता रहे थे। दोनों पक्षों के बीच इसी को लेकर कई दिन से विवाद चल रहा था। देर रात करीब दो बजे अशोक के परिजनों ने जेसीबी मशीन से निर्माणधीन दुकान की दीवार को तोड़ दिया।

मुख्यमंत्री से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात

अच्छा व्यवहार और शुचिता से हर समस्या का होगा समाधान : योगी

- अच्छा व्यवहार करें और कार्यों में शुचिता बरकरार रखें
- आपकी छवि अलग और अतुलनीय बनेगी
- आम आदमी की किसी भी समस्या को छोटी न समझें

लखनऊ। एजेंसी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रशिक्षु अफसरों (2023 बैच) से मुलाकात की। सीएम ने सभी को शुभकामनाएं दीं, फिर अफसरों का मार्गदर्शन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद, अच्छा व्यवहार और अपने कार्यों में शुचिता बनाए रखें, इससे हर समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान फील्ड में किए गए कार्यों के बारे में भी अफसरों से जानकारी ली। शुभकामनाएं देते हुए बोले कि बेहतरीन पारी खेलिए और कुछ नयापन दीजिए।

अभी से तय कीजिए दृष्टि और दिशा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ी ताकत है। फील्ड में जब भी जाएं तो आमजन से संवाद स्थापित करें। संवाद शून्य होने से लोगों में असंतोष होता है। उनसे अच्छा व्यवहार करें और कार्यों में शुचिता बरकरार रखें। इससे आपकी छवि अलग और अतुलनीय बनेगी। आम आदमी की किसी भी समस्या को छोटी न समझें, क्योंकि पीड़ित के लिए वह समस्या काफी मायने रखती है। समस्या का समाधान हो जाता है तो वह अधिकारी आमजन का विश्वास हासिल कर लेता है। जमीनी धरातल पर जुड़े लोगों से कभी कटें नहीं। किसी भी समस्या को बड़ी न बनने दें, बल्कि संवाद के जरिए उसका तत्काल रास्ता निकालें। प्रशिक्षु अधिकारी जनप्रतिनिधियों से भी संवाद स्थापित करें।

राहुल गांधी के बयान का भाजपा उठा रही फायदा, सत्ता-विपक्ष रहे गंभीरः मायावती

लखनऊ। एजेंसी

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान का भाजपा फायदा उठाने में जुट गई है। उन्होंने नसीहत दी है कि सत्ता व विपक्ष दोनों को सदन के भीतर व बाहर गंभीर होने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सोमवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने हिन्दू व हिन्दुत्व को लेकर जो कुछ भी कहा उसका भाजपा फिर से राजनीतिक फायदा उठाने में लग गयी है। कांग्रेस द्वारा इनको ऐसा करने का अवसर प्रदान करना कितना उचित यह सोचने की बात है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने देश में विभिन्न धर्मों के करोड़ों लोगों के हित, कल्याण, भाईचारा आदि के लिए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर संविधान बनाकर सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित किया है। इसके प्रति सत्ता व विपक्ष दोनों को सदन के भीतर व बाहर गंभीर होने की जरूरत।

राहुल गांधी की संसद से तत्काल रद्द होनी चाहिए सदस्यता : जितेन्द्र दास

कानपुर। नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से लोकसभा के सांसद राहुल गांधी के हिन्दू विरोधी दिए बयान पर संतों ने घोर आपत्ति जतायी है। कानपुर पनकी स्थित हनुमान मंदिर के महंत जितेन्द्र दास ने मांग किया है कि राहुल गांधी के संसद सदस्यता तत्काल रद्द कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे प्रतिष्ठत पद पर बैठने योग्य नहीं है। वह मूर्ख और पागल किश्म के व्यक्ति हैं। इनके दिमाग का उपचार होना चाहिए।

विदेशी महिला का बेटा कभी नहीं हो सकता राष्ट्र भक्त : प्रबोधानंद

हरिद्वार। एजेंसी

हिन्दुओं को लेकर संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर जहां हिन्दू समाज में उबाल है, वहीं हरिद्वार के संतों में भी रोष उत्पन्न हो गया। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर हरिद्वार स्थित प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के महामण्डलेश्वर स्वामी रूपेन्द्र प्रकाश महाराज व जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद महाराज ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। स्वामी प्रबोधानंद महाराज ने तो उन्हें पागल तक करार दे दिया। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार में पत्रकार वार्ता कर आश्रम के महंत स्वामी रूपेन्द्र प्रकाश महाराज ने कहा कि राहुल गांधी का बयान हिन्दू समाज पर कुठाराघात है। राहुल ने देश की संसद में खड़े होकर ऐसी घटिया बयानबाजी से पूरे देश के हिन्दुओं का अपमान किया है। इसके लिए उनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसे लोग हिन्दू समाज को लेकर ऐसी अनर्गल व असहनीय बाते करते हैं लेकिन जिस दिन हिन्दू हिंसक हो गया उस दिन उनका हिंदुस्तान में रहना भी दूभर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में देश ने सिक्खों पर अत्याचार व इमरजेंसी जैसी राजनीतिक विभीषिका देखी।

कांग्रेस के राज में जितने सिखों को मारो उतना बड़ा ईनाम पाओ का चलन था। कांग्रेस ने निहत्थे हजारों सिखों का कत्ल कराया। इस कारण पूरी कांग्रेस हिसंक है। राहुल गांधी ने हिन्दुओं के खिलाफ बयान देकर अपनी हिन्दू विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही हिन्दू विरोधी रही है।

हिन्दू रक्षा सेना के राष्ट्राध्यक्ष व जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि हिन्दुओं को लेकर राहुल गांधी का बयान उनकी मानसिकता का परिचायक है। इससे ये साफ हो गया कि उनकी मानसिकता बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने राहुल के डीएनए पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी जो खुद को हिन्दू कहते हैं उनके डीएनए की जांच होनी चाहिए कि वह हिन्दू है भी या नहीं। प्रबोधानंद ने राहुल को पागल तक करार देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति की जगह संसद नहीं, बल्कि पागलखाने में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिन्दू नाम रखकर घूम रहे हैं जबकि उनका दादा पारसी, नानी इसाई और खुद ईसाइ मां के बेटे हैं।

राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए : भूपेन्द्र सिंह

लखनऊ। एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि संसद में राहुल गांधी का भाषण झूठ व निराशा भरा रहा। उन्होंने सम्पूर्ण हिन्दू समाज को हिंसक बताकर घोर अपमान किया है। इससे संपूर्ण हिन्दू समाज आहत है। बोलने से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस के नेताओं से ज्ञानवर्धन करना चाहिए। उनका भाषण संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं था। इस कृत्य के लिए उन्हें अविलम्ब देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस बार-बार हिन्दुओं को अपमानित करती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संतों पर गोली चलवाई थीं। वहीं कांग्रेस केरल में सहयोगी पार्टियों द्वारा की जाने वाली हिंसा पर चुप्पी साध लेती है। पी.चिदम्बरम ने भी हिन्दुओं को आतंकवादी कहा था। राहुल गांधी ने भी पहले कहा था कि मंदिर जाने वाले इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। कांग्रेस नेताओं के इस प्रकार के बयानों से सम्पूर्ण समाज आहत है। भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष पर भी गैर जिम्मेदरान टिप्पणी की है। पहले जब राहुल केवल सांसद थे तब उनके भाषणों में नाटकीय झलकता था। आज वह विपक्ष के नेता हैं।

करनाल में रेलवे ट्रैक पर गिरे कंटेनर, तीन किलोमीटर ट्रैक डैमेज

चंडीगढ़। अमृतसर-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर करनाल के निकट मंगलवार की सुबह चलती हुई मालगाड़ी से करीब आठ कंटनेर रेलवे ट्रैक पर गिर गए। इससे रेलवे ट्रैक व बिजली की लाइन को काफी नुकसान पहुंचा है। करनाल के तरावड़ी के निकट यह हादसा होने के बाद दिल्ली-अमृतसर के बीच चलने वाली दो ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया जबकि कई यात्री व मालगाड़ियों को रद्द करना पड़ा। रेलवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सुबह चार बजे डाउन ट्रैक अंबाला से दिल्ली की ओर खाली कंटेनरों से लदी मालगाड़ी जा रही थी। जब मालगाड़ी तरावड़ी रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तो उसकी पिछली बोगी के पहिए ट्रैक से नीचे उतर गए। मालगाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रैक से पहिए उतरने के बाद भी ट्रेन करीब डेढ़ किलोमीटर बाद रुकी। सूचना पाकर जीआरपी तथा रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कंटेनरों को ट्रैक से हटाने का काम किया जा रहा है। सूचना यह भी है कि मालगाड़ी के पिछले पहिये डिरेल हुए हैं। शुरूआती जांच में सामने आया है कि एक्सल टूटने के कारण यह हादसा हुआ है।

समग्र विकास के लिए एमएसएमई पर सरकार का फोकस : राजेंद्र

भोपाल। एजेंसी

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। पूर्व में प्रदेश में सड़कों की स्थिति और अन्य अधोसंरचनात्मक सेवाओं की स्थिति अत्यंत कमजोर स्थिति में थी, जो प्रदेश में विकास की धीमी गति का कारक थी। आज हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, पॉवर सरप्लस स्टेट हैं। आज 4-लेन, 6-लेन की विश्वस्तरीय सड़कें बन गयी हैं। हवाई अड्डे, रेलवे अधोसंरचनाओं में विकास हुआ है।

सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। नागरिकों की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है। कृषि विकास से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश बीमारू राज्य से सबसे तेज गति से प्रगति करने वाले राज्यों में शामिल है। उप-मुख्यमंत्री शुक्ल सोमवार देर शाम भोपाल में एक निजी चैनल द्वारा आयोजित एमएसएमई समिट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में समग्र विकास को सुनिश्चित करना है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है तो हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति एवं पर्यटन क्रांति जरूरी है। मध्यप्रदेश में इन तीनों क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। औद्योगिक क्रांति सिर्फ बड़ी औद्योगिक इकाइयों से संभव नहीं, समग्र विकास के लिए रोजगारों के सृजन के लिए एमएसएमई पर फोकस महत्वपूर्ण है, यह समय की भी माँग है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। सूक्ष्म, मध्यम और लघु इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता के साथ प्रक्रियाओं को सहज किया गया है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी पहचान स्थापित करने के प्रयास किए गये हैं।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में प्लग एंड प्ले आधार पर आधारभूत संरचनाएं प्रदान की गयी है जिससे सहजता से एमएसएमई क्षेत्र के उद्योग प्रारंभ किए जा सके।

स्वीडन में पितृत्व अवकाश को मान्यता देने वाला नया कानून लागू

कोपेनहेगन। स्वीडन ने सोमवार को पितृत्व अवकाश का नया कानून लागू किया, जिसके तहत दादा-दादी को बच्चे के जन्म के प्रथम वर्ष के दौरान तीन महीने तक अपने पोते-पोतियों की देखभाल करने के लिए वेतन सहित पितृत्व अवकाश लेने की अनुमति दी जाएगी। स्वीडन की 349 सीटों वाली संसद 'रिक्सडाग' ने पिछले साल दिसंबर में पितृत्व भत्ते के हस्तांतरण पर सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह कानून लागू किया गया है। इस कानून के तहत, माता-पिता अपने पितृत्व अवकाश भत्ते का कुछ हिस्सा बच्चे के दादा-दादी को हस्तांतरित कर सकते हैं। एक सरकारी एजेंसी के अनुसार, एक अभिभावक दम्पती अधिकतम 45 दिन की छुट्टी दूसरों को हस्तांतरित कर सकता है, जबकि एकल अभिभावक 90 दिन की छुट्टी हस्तांतरित कर सकता है। करीब एक करोड़ की आबादी वाला यह स्कैंडिनेवियाई देश करदाताओं द्वारा वित्तपोषित सामाजिक कल्याण प्रणाली के लिए जाना जाता है।

इजराइल पर गाजा से रॉकेटों की बौछार, रफाह पर टैंकों से जवाबी हमला

यरुशलम। एजेंसी

इजराइल पर गाजा के फलस्तीनी सशस्त्र संगठन इस्लामिक जिहाद ने रॉकेटों से हमला किया। हालांकि इस हमले में हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं गाजा सिटी के उपनगर शेजया और रफाह पर इजराइली सेना ने टैंकों से जवाबी बड़े हमले किए हैं। ईरान समर्थित इस्लामिक जिहाद ने कहा कि फलस्तीनी लोगों पर इजराइल के अत्याचार के जवाब में लड़ाकों ने रॉकेट हमले किए हैं। इजराइली सेना ने कहा है कि गाजा से इजराइल पर करीब 20 रॉकेट दागे गए लेकिन उनसे कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस हमले ने यह जता दिया है कि लड़ाकों के पास अभी भी इजराइल पर हमले की क्षमता है। सेना ने कहा कि हम फलस्तीनी आतंकियों की इसी क्षमता को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच इजराइली टैंक गाजा सिटी के उपनगर शेजया में और भीतर तक घुस गए हैं और वहां पर गोलाबारी कर रहे हैं। वहां पर पांच दिनों से इजराइली सेना और फलस्तीनी लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी है।

इजराइली सेना ने कहा है 0कि शेजया में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं और काफी हथियार बरामद किए गए हैं। मिस्त्र की सीमा पर स्थित रफाह में भी इजराइली सेना टैंकों से गोलाबारी कर रही है। हमास ने दावा किया है कि वहां पर इजराइली सैनिकों को एक मकान में फंसाकर उस मकान को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया।

कार्यक्रम | डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन

भाजपा सरकार ने लोगों के हितों के लिए यह फैसला लियाः मयंकेश्वर

- धारा 370 और 35-ए की समाप्ति एवं जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन भारत के इतिहास में ऐसा ही एक अद्भुत निर्णय है

मीरजापुर। एजेंसी

नगर के बरौधा कचार स्थित भाजपा कार्यालय के सभागार में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मंगलवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने डा. मुखर्जी को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र के इतिहास में विरले ही ऐसे क्षण आते हैं,जब एक अद्भुत निर्णय से उसका प्रारब्ध निर्मित हो जाता है। ऐसे निर्णयों से इतिहास की धारा मुड़ जाती है। राष्ट्र की यात्रा एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से अनुप्राणित हो उठती है। सफलताओं और उपलब्धियों की गाथा का प्रभाव समस्त राष्ट्र जीवन पर पड़ता है। पूरा राष्ट्र इसके प्रभाव से पुष्पित और पल्लवित हो उठता है। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35-ए की समाप्ति एवं जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन भारत के इतिहास में ऐसा ही एक अद्भुत निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जिसके लिए पूरा राष्ट्र सात दशकों से प्रतीक्षारत था। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय के लिए अत्यधिक दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति एवं एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण और दृढ़ निश्चयी हो। जैसे ही यह निर्णय लिया गया और जिस क्षण संसद के दोनों सदनों ने इसपर विचार करके पारित किया, पूरे देश ने एकजुट होकर इसका उत्सव मनाया। इतिहास के पृष्ठों में वे क्षण स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुके हैं। अनुच्छेद 370 और 35-ए का हटाया जाना हमारे प्रेरणास्त्रोत पुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि है।

उन्होंने कहा कि डा.श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर से रक्तपात भरे युग का अंत हुआ है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबंध था जिसको कभी न कभी हटना ही था। लेकिन, पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लालच में उसको हटाने की हिम्मत नहीं की। भाजपा की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए यह फैसला लिया। इस राज्य में 70 साल तक कश्मीरियत में गरीबी घर कर गई, जिसको प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति ने हटाया।

पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने नौ आतंकवादी मार गिराए

इस्लामाबाद। एजेंसी

पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर और लक्की मारवत जिलों में नौ आतंकवादियों को मार गिराया। यह जानकारी इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने विज्ञप्ति में दी। मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने सोमवार को खैबर के तिराह इलाके में खुफिया अभियान में खूंखार आतंकवादी कमांडर नजीब उर्फ अब्दुर रहमान और आतंकवादी कमांडर इशफाक उर्फ मुआविया सहित सात आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इनके पास से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद हुआ है। इसके अलावा लक्की मारवत जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए। उधर, डेरा इस्माइल खान की कुलाची तहसील के मद्दी इलाके में एक लक्षित हमले में एफसी का एक अधिकारी शहीद हो गया।

नेपाल में तीन माह पुराना गठबंधन टूटा

काठमांडू। नेपाल में तीन माह पुराना सत्ता गठबंधन आखिरकार टूट गया। आधीरात नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस के बीच नए सत्ता समीकरण के लिए समझौता हुआ है। एमाले अध्यक्ष केपी ओली और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा के बीच केंद्र से प्रदेश सरकारों के नेतृत्व परिवर्तन करने को लेकर सहमति हुई है। नई सहमति के मुताबिक अब केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री होंगे। इस बात पर सहमति बनी है कि तीन प्रदेशों में एमाले और तीन प्रदेशों में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाएगा। केंद्र में नेपाली कांग्रेस को 10 मंत्रालय, एमाले को प्रधानमंत्री सहित नौ मंत्रालय और मधेशी पार्टी को छह मंत्रालय दिए जाएंगे। नेकपा एमाले प्रचंड सरकार से समर्थन वापस लेगी। इसके लिए एमाले ने संसदीय दल की बैठक आहूत की है।

अपने अंतिम भाषण में मुख्य कोच द्रविड़ ने पूरी भारतीय टीम का आभार जताया

● नया मुख्य कोच जुलाई के अंत में श्रीलंका दौरे के दौरान कार्यभार संभालेगा
● 6 जुलाई से शुरू होने वाली टी20आई सीरीज के लिए नई टीम के साथ जिम्बाब्वे जाएंगे

नई दिल्ली। एजेंसी

आईसीसी टी 20 विश्व कप जीतने और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में अपने कार्यकाल के समापन के बाद, महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने खिताब जीतने वाली टीम के सामने अपना अंतिम भाषण दिया, और उन्हें उनके समय और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। टी20 विश्व कप खिताब जीतने के बाद, द्रविड़ का भारत के मुख्य कोच के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया है। गौतम गंभीर और डब्ल्यूवी रमन को पुरुष टीम के मुख्य कोच पद का अगला दावेदार माना जा रहा है। नया मुख्य कोच जुलाई के अंत में श्रीलंका दौरे के दौरान कार्यभार संभालेगा। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण 6 जुलाई से शुरू होने वाली टी20आई सीरीज के लिए नई टीम के साथ जिम्बाब्वे जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक वीडियो में, द्रविड़ ने कहा कि उनके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं और उन्होंने टीम के सभी सदस्यों को उनके समय के लिए धन्यवाद दिया। द्रविड़ ने कहा मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे इस अविश्वसनीय याद का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप सभी को ये पल याद होंगे। मुझे लगता है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, यह रनों के बारे में नहीं है, यह विकेटों के बारे में नहीं है, आप अपने करियर को कभी याद नहीं रखेंगे। लेकिन आप इस तरह के पलों को याद रखेंगे। तो चलिए हम इसका भरपूर आनंद लेते हैं।

मुझे आप लोगों पर इससे ज्यादा गर्व नहीं हो सकता। जिस तरह से आपने वापसी की, जिस तरह से आपने संघर्ष किया। जिस तरह से हमने एक टीम के रूप में काम किया, जिस तरह से आपने दृढ़ता दिखाई। पिछले कुछ सालों में कुछ निराशाएं हुई हैं जहाँ हम करीब पहुँच कर भी लक्ष्य को पार नहीं कर पाए हैं। लेकिन इन लड़कों ने जो किया है, आप सभी ने जो किया है, सपोर्ट स्टाफ में सभी ने जो किया है, हमने जो कड़ी मेहनत की है, हमने जो बलिदान दिए हैं। आप जानते हैं, मुझे लगता है... पूरे देश को आप सभी पर और आपने जो हासिल किया है, उस पर गर्व है।

द्रविड़ ने कहा कि खिलाड़ियों और उनके परिवारों, चाहे वे उनके माता-पिता हों, पत्नियां हों, भाई-बहन हों, ने अपने जीवन में लंबे समय तक बहुत त्याग किए, ताकि वे एक साथ इस पल का आनंद ले सकें। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद टीम न छोड़ने के लिए राजी किया।

जिम्बाब्वे दौरे के लिए सुदर्शन, जितेश, हर्षित भारतीय टीम में शामिल

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दो टी 20 मैचों के लिए संजू सैमसन, शिवम दूबे और यशस्वी जायसवाल के स्थान पर सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन, विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा और तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भारतीय टीम में शामिल किया है। पांच मैचों की सीरीज का पहला मैच 6 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। आखिरी टी20 मैच 14 जुलाई को उसी मैदान पर खेला जाएगा, जहां सभी पांच मैच खेले जाएंगे। आईसीसी टी-20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम के सैमसन, दुबे और यशस्वी फिलहाल तूफान बेरिल के कारण बारबाडोस में फंसे हुए हैं। बीसीसीआई ने मंगलवार को एक बयान में कहा, पुरुष चयन समिति ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दो टी-20 मैचों के लिए संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की जगह साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को शामिल किया है। संजू, शिवम और यशस्वी आईसीसी टी-20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के बाकी सदस्यों के साथ पहले भारत आएंगे और फिर उसके बाद हरारे के लिए रवाना होंगे।

एक नजर

विंबलडन 2024: जननिक सिनर ने हन्फमैन को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया

लंदन। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी इटली के जननिक सिनर ने सोमवार रात विंबलडन के पहले दौर में गैरवरीय जर्मन खिलाड़ी यानिक हन्फमैन को 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया, जहां उनका सामना हमवतन मैटियो बेरेटिनी से होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन ने अपने शक्तिशाली सर्विस और फोरहैंड का इस्तेमाल हन्फमैन के खिलाफ अच्छे प्रभाव के साथ किया और एक ब्रेक के दम पर पहला सेट आसानी से जीत लिया और अगले सेट में जल्दी ही बढ़त हासिल कर ली। हन्फमैन ने सिनर की सर्विस पर दबाव बनाया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाए और 22 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी दो सेट आगे हो गए। दुनिया के 110वें नंबर के खिलाड़ी हन्फमैन ने तीसरे सेट में 4-0 की बढ़त हासिल कर ली और अंत में एक शानदार वॉली के साथ तीसरा सेट अपने नाम कर लिया। हालांकि चौथे सेट में सिनर ने बेहतरीन वापसी की और चौथा सेट आसानी से जीतकर मैच 3-1 से अपने नाम कर लिया। दो सप्ताह पहले हाले में खेल की सबसे चिकनी सतह पर अपना पहला खिताब जीतने वाले सिनर को 2021 के उपविजेता बेरेटिनी के खिलाफ एक और मुश्किल परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने हंगरी के मार्टन फुकसोविक्स को 7-6(3) 6-2 3-6 6-1 से हराया।

पुरूष एकल के पहले दौर में हारे सुमित नागल

लंदन। भारत के शीर्ष वरीयता प्राप्त एकल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल विंबलडन 2024 में पुरुष एकल के पहले दौर में सर्बिया के मिओमिर केकमैनोविच से हार गए। नागल को सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में केकमैनोविच ने 2 घंटे और 48 मिनट तक चले मैच में 2-6, 6-3, 3-6, 4-6 से शिकस्त दी। पिछले महीने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले सुमित नागल ने शानदार खेल दिखाया, पहला सेट 2-6 से हारने के बाद, दूसरे सेट में उन्होंने बेहतरीन वापसी की और दूसरा सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया। हालांकि इसके बाद केकमैनोविच ने शानदार की और तीसरा सेट 3-6 से जीतकर 2-1 की बढ़त बना ली। नागल अंतिम सेट में 1-5 से पीछे थे, लेकिन विश्व के 73वें नंबर के खिलाड़ी ने हार नहीं मानी। नागल ने वापसी की, मैच में बने रहने के लिए संघर्ष किया और बराबरी से एक गेम दूर रह गए। हालांकि, केकमैनोविच ने अपना धैर्य बनाए रखा और चार सेटों में जीत हासिल की। नागल का एकल अभियान समाप्त हो चुका है। लेकिन वह विंबलडन में सर्बिया के डुसन लाजोविच के साथ युगल में खेलेंगे। इंडो-सर्बियाई जोड़ी अपने अभियान की शुरूआत पुरुष युगल के पहले दौर में स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज और जौम मुनार के खिलाफ करेगी।

टी20 विश्वकप की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम

सिडनी। एजेंसी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी20 विश्वकप की तैयारी के लिए अगले माह अगस्त में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी। इस दौरे में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के साथ तीन मैचों की टी20 सीरीज के साथ ही तीन एकदिवसीय के अलावा एक चार दिवसीय मैच भी खेलना है। इससे बांग्लादेश में साल के आखिर में होने वाले टी20 विश्वकप के लिए टीम को अभ्यास का अच्छा अवसर मिलेगा। इसके अलावा उसे अपनी कमियों का भी पता चलेगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसमें ताहलिया मैकग्रा ऑस्ट्रेलियाई 20 और 50 ओवरों की टीम की कप्तानी करेंगी। वहीं चार्ली नॉट को चार दिवसीय मैच के लिए कप्तान बनाया गया है। इस दौर में सभी तीन टी20 मैच ब्रिसबेन में जबकि एकदिवसीय मैच मैके में खेले जाएंगे। एकमात्र चार दिवसीय मैच गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा। पहला टी20 मैच 07 अगस्त , दूसरा टी20 09 अगस्त जबकि तीसरा तीसरा टी20 11 अगस्त को खेला जाएगा।

वहीं पहला एकदिवसीय 14 अगस्त, दूसरा 16 अगस्त को व तीसरा एकदिवसीय 18 अगस्त को खेला जाएगा। एकमात्र चार दिवसीय मैच 22 से 25 अगस्त तक होगा।

टी20 टीम : ताहलिया मैकग्रा (कप्तान), मैडी डार्के, सोफी डे, निकोल फाल्टम, टेस फ्लिंटॉफ, किम गार्थ, चार्ली नॉट, कैटी मैक, ग्रेस पार्सोंस, मेगान शट, कर्टनी सिप्पेल, टायला वी, ताहलिया विल्सन।

एकदिवसीय टीम : ताहलिया मैकग्रा (कप्तान), मेटलान ब्राउन, मैडी डार्के ,सोफी डे, निकोल फाल्टम, टेस फ्लिंटॉफ, किम गार्थ, चार्ली नॉट, कैटी मैक, ग्रेस पार्सोंस, मेगान शट, कर्टनी सिप्पेल, टायला वी, ताहलिया विल्सन।

चार दिवसीय टीम : चार्ली नॉट (कप्तान), मेटलान ब्राउन, मैडी डार्के, सोफी डे, एम्मा डे ब्रूग, निकोल फाल्टम, टेस फ्लिंटॉफ, कैटी मैक, लिली मिल्स, ग्रेस पार्सोस, केट पीटरसन, कर्टनी सिप्पेल, जॉर्जिया वोल।

शुभमन गिल की अगुआई में जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हुई भारतीय क्रिकेट टीम

नई दिल्ली। एजेंसी

शुभमन गिल की अगुआई वाली दूसरी पंक्ति की भारतीय टीम 6 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए मंगलवार को अफ्रीकी देश के लिए रवाना हो गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कई भारतीय क्रिकेटरों और कोच वीवीएस लक्ष्मण के जिम्बाब्वे के लिए रवाना होने की तस्वीरें साझा कीं। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम में चार सलामी बल्लेबाज शामिल हैं, जिनमें यशस्वी जायसवाल, जो टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, शुभमन गिल, रुतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा शामिल हैं। पूरी संभावना है कि गिल और जायसवाल शनिवार को हरारे में होने वाले पहले टी20 मैच में बल्लेबाजी की शुरूआत करेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा के संन्यास के बाद, जिम्बाब्वे में होने वाली सीरीज भारत के टी20 भविष्य की झलक पेश करेगी।

टी20 विश्व कप के सभी स्टैंडबाय - गिल, तेज गेंदबाज आवेश खान, खलील अहमद और फिनिशर रिंकू सिंह के साथ-साथ संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल - जिम्बाब्वे दौरे का हिस्सा हैं। यह सीरीज पूरी तरह से हरारे में आयोजित की जाएगी।

जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम : शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, रुतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे और शिवम दुबे।

बीबीएल : कॉलिन मुनरो ने 2026 तक ब्रिस्बेन हीट के साथ दोबारा किया करार

ब्रिस्बेन। एजेंसी

बिग बैश लीग (बीबीएल) टीम ब्रिसबेन हीट ने न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज कोलिन मुनरो के साथ दो सत्रों के लिए दोबारा करार किया है। क्लब ने मंगलवार को उक्त घोषणा की। न्यूजीलैंड की टी-20 विश्व कप टीम में जगह नहीं बना पाने के बाद इस वर्ष की शुरूआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मुनरो ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में 428 टी-20 मैच खेले हैं और 141.25 के स्ट्राइक रेट से 10,961 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और 67 अर्धशतक शामिल हैं। 37 वर्षीय खिलाड़ी हीट के साथ अपने तीसरे सीजन के लिए तैयार हैं और नए नियमों के तहत साइन किए जाने वाले बीबीएल के चौथे खिलाड़ी हैं, जो प्रत्येक क्लब को विदेशी खिलाड़ी ड्राफ्ट से पहले बहु-वर्षीय सौदे पर एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को साइन करने की अनुमति देता है।

मुनरो, जो पर्थ स्कॉर्चर्स की 2021-22 बीबीएल खिताबी जीत के सदस्य थे, ने पिछले दो सीजन हीट के साथ खेले हैं और 98 और नाबाद 99 रनों की धमाकेदार पारियों के साथ 502 रन बनाए हैं। दोनों सीजन में वह यूएई-आधारित आईएलटी20 में डेजर्ट वाइपर्स में शामिल होने के लिए जल्दी चले गए, लेकिन उनका नया हीट करार यह सुनिश्चित करेगा कि मुनरो फाइनल सहित सभी बीबीएल मैचों के लिए उपलब्ध रहें।

इंग्लैंड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और पूर्व हीट स्टार सैम बिलिंग्स अगले सीजन में सिडनी थंडर से जुड़ेंगे, जबकि हीट के कल्ट हीरो और पिछले सीजन के फाइनल के हीरो जोश ब्राउन मेलबर्न रेनेगेड्स से जुड़ेंगे। मुनरो ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा और मैट रेनशॉ के साथ मिलकर हीट की मजबूत लाइन-अप की अगुआई करेंगे। हीट के पास अगले सीजन के लिए जोहान बोथा के रूप में एक नया कोच है, जिन्होंने वेड सेकोम्बे की जगह ली है।

यूरो 2024 : पुर्तगाल ने स्लोवेनिया को पेनल्टी शूटआउट में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

बर्लिन। एजेंसी

पुर्तगाल ने सोमवार को फ्रैंकफर्ट के ड्यूश-बैंक-पार्क में यूरो 2024 के अंतिम 16 मैच में स्लोवेनिया को पेनल्टी शूटआउट मे 3-0 से हराकर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। पुर्तगाल की इस जीत के हीरो गोलकीपर डिओगो कोस्टा रहे, जिन्होंने शूटआउट में तीन पेनल्टी बचाए। पुर्तगाल ने मैच की शुरूआत से ही गेंद पर कब्जा जमाया और शुरूआती चरणों में स्लोवेनिया को पीछे धकेल दिया। हालांकि, इसके बावजूद पुर्तगाली टीम को अपने दबदबे को गोल में बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडीस दोनों ने नजदीकी मौकों को गंवा दिया। स्लोवेनिया ने अपने सभी खिलाड़ियों को गेंद के पीछे रखते हुए दृढ़ता से बचाव किया। रोनाल्डो के पास 30वें मिनट में फ्री-किक से एक मौका था, लेकिन उन्होंने इस मौके को भी गंवा दिया।

पहले हाफ के अंतिम चरण में स्लोवेनिया पुर्तगाल को चकमा दे सकता था, लेकिन पेटर स्टोजानोविक ने गोल पर शॉट लेने के बजाय स्क्वायर पास का विकल्प चुना। पहला हाफ गोलरहित समाप्त हुआ। मैच दोबारा शुरू होने के बाद भी पुर्तगाली टीम अधिक सक्रिय टीम बनी रही, जबकि स्लोवेनिया काफी हद तक निष्क्रिय रही।

मैच के 55वें मिनट में स्लोवेनिया के गोलकीपर, जान ओब्लाक ने रोनाल्डो की फ्री किक का शानदार बचाव किया और पुर्तगाल एक बार फिर खाता खोलने से चूक गया। अतिरिक्त समय में, रोनाल्डो के पास गतिरोध को तोड़ने का सुनहरा अवसर था जब डिओगो को बॉक्स के अंदर फाउल किया गया था।

वाणिज्य

डिवाइन पावर की 287.5 प्रतिशत के प्रीमियर पर लिस्टिंग

नई दिल्ली। एजेंसी

घरेलू शेयर बाजार में आईपीओ के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों को लगातार मुनाफा हो रहा है। डिवाइन पावर के शेयरों की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के एसएमई प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार लिस्टिंग हुई। इसके साथ ही पेट्रो कार्बन एंड केमिकल्स, द मनी फेयर (अकीको ग्लोबल सर्विसेज) और एलायड ब्लेंडर्स के शेयरों की भी जोरदार लिस्टिंग हुई।

अल्युमिनियम और तांबे के वाइंडिंग तार और स्ट्रिप तैयार करने वाली कंपनी डिवाइन पावर के शेयर आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 155 रुपये के स्तर पर लिस्ट हुए। आईपीओ के जरिए कंपनी के शेयर 40 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। इस तरह लिस्टिंग के साथ ही आईपीओ के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों को 287.5 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन मिल गया। शुरूआती कारोबार में खरीदारी के सपोर्ट से ये शेयर 306.88 प्रतिशत की उछाल के साथ 162.75 रुपये के अपर सर्किट तक पहुंच गया।

डिवाइन पावर का 22.56 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 27 जून के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खोला गया था। इस आईपीओ को ओवरऑल 393.67 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन मिला था। सिर्फ खुदरा निवेशकों के हिस्से में ही ये आईपीओ 507.94 गुना का ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के जरिए 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 56.90 लाख शेयर जारी किए गए हैं। कंपनी की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक इन शेयरों के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

इसी तरह से एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर आज पेट्रो कार्बन एंड केमिकल्स के शेयरों की 75.4 प्रतिशत के प्रीमियर के साथ लिस्टिंग हुई। आईपीओ के जरिए इस कंपनी के शेयर 171 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे लेकिन इसकी लिस्टिंग 300 रुपये के भाव पर हुई।

एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का शेयर करीब 14 फीसदी उछाल के साथ सूचीबद्ध

मुंबई/नई दिल्ली। एजेंसी

● कंपनी का बाजार मूल्यांकन (मार्केट कैप) 8,869.61 करोड़ रुपये रहा

एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड (एबीडी) का शेयर 281 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले करीब 14 फीसदी की उछाल के मंगलवार को शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन (मार्केट कैप) 8,869.61 करोड़ रुपये रहा। ऑफिसर्स च्वॉइस व्हिस्की बनाने वाली कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर निर्गम मूल्य से 13.20 फीसदी बढ़कर 318.10 रुपये पर खुला। इसके बाद ये 14.73 फीसदी की बढ़त के साथ 322.40 रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर इसका शेयर 13.87 फीसदी की उछाल के साथ 320 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड के आईपीओ) को गत गुरुवार को बोली के अंतिम दिन 23.49 गुना अभिदान मिला था। इसके आईपीओ में एक हजार करोड़ रुपये तक का नया निर्गम और 500 करोड़ रुपये तक की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। इसका मूल्य दायरा 267-281 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इसके अलावा कंपनी ने एंकर (बड़े) निवेशकों से 449 करोड़ रुपये जुटाए हैं। उल्लेखनीय है कि एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड को एबीडी के तौर पर जाना जाता है। कंपनी नए निर्गम से प्राप्त राशि में 720 करोड़ रुपये का उपयोग कर्ज के भुगतान और एक हिस्सा सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करेगी।

रिकॉर्ड बनाने के बाद फिसले सेंसेक्स और निफ्टी

नई दिल्ली। एजेंसी

घरेलू शेयर बाजार में कारोबार के दौरान दबाव बना हुआ नजर आ रहा है। कारोबार की शुरूआत ऑल टाइम हाई के नए रिकॉर्ड के साथ हुई। सेंसेक्स और निफ्टी ने लिवाली के सपोर्ट से और तेजी हासिल करके मजबूती का नया रिकार्ड बनाने में भी सफलता पाई। इसके बाद मुनाफा वसूली शुरू हो जाने से थोड़ी देर में ही ये दोनों सूचकांक गिर कर लाल निशान में पहुंच गए। पहले 1 घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.05 प्रतिशत और निफ्टी 0.07 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरूआती एक घंटे का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से ओएनजीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इंफोसिस और विप्रो के शेयर 2.20 प्रतिशत से लेकर 1.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और कोटक महिंद्रा के शेयर 2.26 प्रतिशत से लेकर 1.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आ रहे थे।

अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,248 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी।

इनमें से 1,434 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 814 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 14 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 16 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि निफ्टी में शामिल शेयरों में से 21 शेयर हरे निशान में और 29 शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे थे। बीएसई का सेंसेक्स आज ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बनाते हुए 364.18 अंक की तेजी के साथ 79,840.37 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरूआत होते ही ये सूचकांक उछल कर अभी तक के सर्वोच्च स्तर 79,855.87 अंक तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद मुनाफा वसूली शुरू हो जाने के कारण इस सूचकांक में गिरावट आ गई।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रवीण गुप्ता बने सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव

लंबा प्रशासनिक अनुभव सार्वजनिक निर्माण विभाग को ले जाएगा प्रगति की राह पर

चमकता राजस्थान

जयपुर। राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र से पहले आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस लिस्ट में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे प्रवीण गुप्ता को पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव पद पर पोस्टिंग दी गई है।

आईएएस प्रवीण गुप्ता एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले राजस्थान कैडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। राजस्थान सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। उनकी पहचान ब्यूरोक्रेसी और आमजन में एक बोल्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड, बेहतरीन निर्णय क्षमता वाले निर्विवाद ऑफिसर के रूप में है। उनके राज्य के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी रहते राजस्थान के निर्वाचन विभाग को बेहतरीन कार्य के लिए सराहा गया है। खासकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस प्रवीण गुप्ता के नवाचारों और वर्किंग स्टाइल की भारत निर्वाचन आयोग ने जमकर तारीफ की है। साल 1995 बैच के आईएएस अधिकारी प्रवीण गुप्ता साल फरवरी 2020 से जुलाई 2020 तक जांच विभाग में कमिश्नर रहे हैं। इसके अलावा वे रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में सदस्य, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आयुक्त के अलावा मुख्यमंत्री ऑफिस में विशेष सचिव और उप सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। इससे पहले वे भरतपुर और झालावाड़ के कलेक्टर भी रह चुके हैं।

निर्वाचन विभाग की ओर से दी गई प्रवीण गुप्ता को विदाई

पदस्थापन आदेश के बाद प्रमुख शासन सचिव प्रवीण गुप्ता को निर्चाचन विभाग की ओर से राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद से विदाई दी गई.

प्रवीण गुप्ता को सचिवालय के कांफ्रेंस सभागार में निर्वाचन विभाग के सभी अधिकारियों और कार्मिकों ने एक सादे समारोह में भावभीनी विदाई दी. इस दौरान गुप्ता ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य को न्यूनतम संसाधनों के बावजूद अधिकतम उत्कृष्टता के साथ पूरा करने के लिए बधाई दी और आभार जताया. उन्होंने कहा कि आप लोगों के अथक प्रयासों और मेहनत के परिणामस्वरूप गत लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान राजस्थान के निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हुए कई सफलताएं अर्जित की और देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नए मापदंड स्थापित किए हैं. निर्वाचन विभाग के अधिकरियों ने गुप्ता के साथ बिताए चार वर्षों के कार्यकाल के अनुभव साझा किए और उनकी उल्लेखनीय कार्यनीति और काम के प्रति जूनून की प्रशंसा की. विभाग के विशेषाधिकारी सुरेश चन्द्र ने विभाग के सभी कार्मिकों की ओर से आश्वासन दिया कि श्री गुप्ता के नेतृत्व में विभाग में अटूट समर्पण, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता से जो उच्च मानक स्थापित हुए हैं, वे आगे भी जारी रहेंगे.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिन्दू विरोधी बयान के बाद भाजयुमो ने राहुल गांधी का फूंका पुतला

हिंदू समाज को हिंसक कहने वाले राहुल गांधी एक समुदाय विशेष के लिए हिन्दुओं का कर रहे है अपमानः अंकित गुर्जर चेची

चमकता राजस्थान

जयपुर, 02 जुलाई2024। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर राहुल गांधी का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेताओं से माफी मांगने की मांग की।

भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिन्दुओं को हिंसक बताया और हिन्दुओं का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी

को सार्वजनिक रूप से हिन्दुओं के खिलाफ दिए गए इस बयान को वापस लेते हुए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी हाय हाय, गर्व से कहो हम हिन्दू हैं, राहुल गांधी माफी मांगों जैसे नारे लगाए। इस दौरान जयपुर शहर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पुरूवंशी, विक्रम चौधरी, कमल स्वामी, भुवनेश गुप्ता, भीमराज मीणा, भरत सिंह, सुरज घोडीवाल, राजवीर राठौड, विजेंद्र महावा, अमित चौधरी, अर्पित शर्मा, पवन शर्मा, दीपक शर्मा, लोहित सिंह, आशीष शर्मा, हर्षित तिवाड़ी सहित युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गरीब कन्याओं के विवाह से शुरू हुआ अंबानी परिवार का शादी समारोह

चमकता राजस्थान

मुंबई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी की रस्मों की शुरुआत गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह से हुई। वंचित परिवारों से जुड़े 50 से अधिक जोड़े मुंबई से कोई 100 किलोमीटर दूर पालघर से आए थे। सामूहिक विवाह का आयोजन रिलायंस कॉरपोरेट पार्क में किया गया। इस सामूहिक विवाह में वर व वधू पक्ष के करीब 800 लोग शरीक हुए। इस मौके पर अंबानी परिवार ने ऐसे कई सामूहिक विवाह करवाने का संकल्प लिया। सामूहिक विवाह के अवसर पर नीता अंबानी व मुकेश अंबानी अपने परिवार के सदस्यों के साथ शामिल हुए। नव विवाहितों को अंबानी परिवार ने शुभकामनाएं दी।

अंबानी परिवार की ओर से प्रत्येक जोड़े को मंगलसूत्र, शादी की अंगूठी और नाक की लोंग सहित सोने-चांदी के कई आभूषण भेंट किए। इसके अलावा, प्रत्येक दुल्हन को 'स्त्रीधन' के रूप में 1 लाख 1 हजार रुपये का चेक भी दिया गया। प्रत्येक जोड़े को एक वर्ष के लिए पर्याप्त किराने और घरेलू सामान भी उपहार में दिए गए, जिसमें 36 प्रकार की आवश्यक वस्तुएं जैसे बर्तन, गैस स्टोव, मिक्सर, गद्दे, तकिए आदि शामिल थे। सामूहिक विवाह में उपस्थित लोगों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन भी किया गया। शाम को हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में वारली जनजाति द्वारा पारंपरिक तरपा नृत्य प्रस्तुत किया गया। बताते चलें कि अंबानी परिवार हर बड़े पारिवारिक कार्यक्रम की शुरूआत मानव सेवा से करता है। पहले भी परिवार में शादियों के अवसर पर, अंबानी परिवार ने आस-पास के समुदायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर लोगों के लिए भोजन सेवा या अन्न सेवा चलाई थी।

संसद में राहुल गॉधी ने भाजपा को आईना दिखा उनकी नाक में नकेल डालने का कार्य किया : डोटासरा

चमकता राजस्थान

जयपुर, 02 जुलाई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गॉधी पर दिये गये वक्तव्य पर पलटवार करते हुये संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय नेतृत्व से प्राप्त पर्ची पढ×कर दिये गये वक्तव्य ने साबित कर दिया कि राजस्थान में वास्तविक रूप से पर्ची सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास प्रेसवार्ता करने हेतु कोई मुद्दा नहीं था किन्तु दिल्ली से आई पर्ची को पढ×कर उन्होंने धन्यवाद और चलो-चलो कहकर अपना सम्बोधन समाप्त किया। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को पर्ची लिखकर दी उसने पर्ची बनाने में किसी तरह से बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गॉधी ने जो मुद्दे संसद में उठाये वे सभी जनता के मुद्दे थे और जनता की आवाज बनकर राहुल गॉधी ने देशवासियों का पक्ष तथा पिछले 10 साल के मोदी सरकार के शासन की घटनायें संसद में मोदी सरकार से बनी एनडीए सरकार के समक्ष उठाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि राहुल गॉधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा तथा आरएसएस हिन्दू समाज के ठेकेदार नहीं है तथा आरएसएस के स्वयं सेवक एवं भाजपा के नेता ही केवल हिन्दू नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोग हिन्दू समाज के हैं और हिन्दू धर्म को मानते हैं, किन्तु वे भाजपा के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गॉधी ने आरोप लगाया कि हिन्दू के होने के लिये किसी को भाजपा से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है राहुल गॉधी ने कहा कि हिन्दू कभी हिंसा फैलाने में विश्वास नहीं रखता, हिन्दू अहिंसावादी है तथा निडर है। डोटासरा ने कहा कि राहुल गॉधी ने नौजवानों के हितों से जुड़ी हुई अग्रिवीर योजना तथा मणिपुर में माताओं और बहिनों के साथ हुई दुःखद घटना सहित हर उस मुद्दे को नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से रखा जिसका सरोकार जनता से है। उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गॉधी ने किसानों पर थोपे गये तीन काले कानून तथा किसके हित में मोदी सरकार द्वारा उक्त कानून पारित किये गये, इस मुद्दे को भी उठाया, क्योंकि जब किसान आन्दोलन हुआ तो भाजपा के नेताओं ने देश के अन्नदाता को शराबी, डाकू, आतंकवादी, खालिस्तानी ना जाने कितने अपशब्दों से सम्बोधित किया था। उन्होंने कहा कि राहुल गॉधी ने देश के 25 लाख युवा जो कि नीट में हुई चीट से अपना भविष्य अंधकारमय महसूस कर रहे हैं, का पक्ष संसद में रखा, क्योंकि मोदी शासन में 70

पेपर लीक हो गये, किन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेशों में घूमते रहे, लेकिन मोदी ने अपना दो करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने के वादे को निभाने की चिंता नहीं की।

डोटासरा ने कहा कि जब राहुल गॉधी जनता की आवाज संसद में अपने वक्तव्य के माध्यम से उठा रहे थे तब देश के गृह मंत्री अमित शाह तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बैचेनी का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गॉधी के भाषणकाल में एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो संसदीय परम्पराओं के अनुकूल ना हो, प्रक्रिया एवं नियमों के विरूद्ध हो। उन्होंने कहा कि भाजपा का हमेशा से एजेण्डा रहा है कि विपक्ष के नेताओं के भाषण काट-छांट कर सोशल मीडिया पर चलाकर झूठे तथ्य फैलायें जायें किन्तु सोमवार को संसद में राहुल गॉधी ने शेर की तरह दहाड़ते हुये अपना वक्तव्य दिया, जिसे मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों ने सुना और देखा, इसके लिये मीडिया धन्यवाद की पात्र है क्योंकि उन्होंने राहुल गॉधी का भाषण देश की जनता के सामने रखने का कार्य किया और सभी देशवासियों ने राहुल गॉधी के भाषण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राहुल गॉधी जब अपना वक्तव्य संसद में दे रहे थे उस वक्त देश के गृह मंत्री लोकसभा अध्यक्ष से नियमों की दुहाई देते हुये संरक्षण मांग रहे थे और रात को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष दबाव बनाकर नियमों और प्रक्रियाओं के विरूद्ध जाकर राहुल गॉधी के वक्तव्य के कई हिस्से एक्सपंज करवा दिये। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों के मुद्दे राहुल गॉधी के वक्तव्यों से एक्सपंज करवाये, इसके लिये भाजपा को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को वक्तव्य के समय अपनी व्यवस्था देनी चाहिये थी कि भाषण का कौनसा हिस्सा नियम विरूद्ध है अथवा संसदीय परम्पराओं के विरूद्ध है, यदि ऐसा होता तो देश की जनता को जानकारी मिलती कि कौनसा हिस्सा असंसदीय है और यह भी सामने आता कि क्या लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई है। उन्होंने कहा कि रात को लोकसभा अध्यक्ष ने अपना सचिवालय खुलवाकर राहुल गॉधी के वक्तव्य में देश की जनता के उठाये गये, युवाओं की बेरोजगारी, मंहगाई, हिंसा, नफरत, नीट, मणिपुर की घटना आदि मुद्दे जिनसे भाजपा को तकलीफ है, छांट-छांट कर राहुल गॉधी के भाषण से हटाने का कार्य किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री राजस्थान से सवाल करते हुये कहा कि लोकसभा चुनावों के परिणाम के पश्चात से मुख्यमंत्री आहात हैं और अपनी कुर्सी को लेकर बैचेन हैं, किन्तु मुख्यमंत्री महोदय को यह समझना चाहिये कि पॉच साल भाजपा की सरकार चलनी है, लेकिन उन्हें इतना भी बैचेन नहीं होना चाहिये कि दिल्ली से जो पर्ची आये उसमें वह एक शब्द भी अतिरिक्त क्यों नहीं जोड़ पाते। उन्होंने कहा कि प्रेस के साथियों के वाजिब सवाल जो कल राहुल गॉधी के वक्तव्य से संबंधित था, का जवाब दिये बिना मुख्यमंत्री क्यों उठ गये।

उन्होंने कहा कि राहुल गॉधी का कहना है कि भाजपा व आरएसएस हिन्दू समाज के प्रतिनिधि नहीं है क्योंकि देश के दो तिहाई हिन्दूओं ने भाजपा के विरूद्ध मतदान किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के हिन्दू समाज ने भाजपा को लोकसभा चुनाव में धूल चटाई है तथा प्रधानमंत्री वाराणसी बड़े मुश्किल से चुनाव जीत सके, जबकि हिन्दू समाज ने उनके खिलाफ जमकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग का एक मंत्री जिसे दोनों विभाग आरएसएस की मेहरबानी से मिले हैं, कह रहे हैं कि आदिवासी भाई यदि अपने आपको हिन्दू नहीं मानते हैं तो उनका डीएनए टेस्ट करवाकर पता करवायेंगे कि इनका बाप कौन था। उन्होंने कहा कि इससे निम्र स्तरीय मानसिकता का बयान कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कम से कम इस मुद्दे पर पूछे गये सवाल का जवाब तो देना ही चाहिये था। उन्होंने कहा कि इस सवाल से मुख्यमंत्री कितने दिन बचेंगे, क्योंकि बुधवार से विधानसभा सत्र प्रारम्भ हो रहा है और वहॉ उनसे यह सवाल जनता की ओर से पूछे जायेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय छः माह से कुर्सी पर तो बैठे हैं किन्तु उनकी सरकार जनता का कोई कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में आपसी लड़ाई तथा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की अच्छी योजनायें बंद करने के निर्णय ही दिख रहे हैं लेकिन जनहित का एक कार्य भी नजर नहीं आता है, इस पर कांग्रेस पार्टी भाजपा से विधानसभा में प्रश्न करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री प्रदेश में किस-किसका डीएनए टेस्ट करवायेंगे और किस-किसके पिता का पता करेंगे, इस बात की जानकारी भाजपा के मुख्यमंत्री से विधानसभा में मांगी जायेगी। उन्होंने कहा कि कल संसद में राहुल गॉधी ने भाजपा को आईना दिखाया है और उनकी नाक में नकेल डालने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अवगत कराते बताया कि राहुल गॉधी को संस्कार कहॉ से मिले हैं यह जानना चाहते हैं किन्तु उन्हें यह ज्ञात हो कि राहुल गॉधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्रीमती इंदिरा गॉधी ने देश को एक रखने के लिये अपना जीवन कुर्बान कर दिया था, इसी प्रकार उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. राजीव गॉधी ने देश की एकता एवं अखण्डता के लिये अपने जीवन की कुर्बानी दी थी और श्रीमती सोनिया गॉधी ने देश की सर्वोच्च सत्ता को ठुकरा कर त्याग का परिचय दिया था, इन्हीं से राहुल गॉधी को संस्कार मिले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 वर्ष तक सदन में मनमानी कर ली, किन्तु अब राहुल गॉधी के रूप में सदन को नेता प्रतिपक्ष मिला है जिससे भाजपा डरी हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग कर विपक्ष की आवाज दबाने का कार्य भाजपा द्वारा किया गया, किन्तु अब राहुल गॉधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के पश्चात उनके एक दिन के सवालों के जवाब एनडीए की केन्द्र सरकार नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गॉधी के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित पॉच मंत्रियों को उठना पड़ा और आज जब राहुल गॉधी की छवि सोशल मीडिया से नहीं बिगड़ सकती क्योंकि भारी जनसमर्थन राहुल गॉधी के साथ है तो देशभर में भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों को राहुल गॉधी के वक्तव्य के विरूद्ध दुष्प्रचार करने हेतु प्रेस कान्फ्रेंस करने का आदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास हिन्दू समाज का ठेका नहीं है, हम सब हिन्दू हैं और हिन्दू होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमें भाजपा से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष से जिस प्रकार तानाशाहीपूर्ण सरकार चली और संवैधानिक संस्थाओं की साख खत्म करने का कार्य हुआ उससे पूरा देश उद्वेलित है। उन्होंने कहा कि जबरन बिना नियम कानून की पालना किये बगैर राहुल गॉधी के भाषण के अंश हटा दिये गये जो निन्दनीय है। उन्होंने कहा कि मोदी शासन में 70 पेपर आउट हुये और युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ, जब राहुल गॉधी ने इस पर प्रश्न पूछा तो प्रधानमंत्री बगले झांकने लग गये। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने इसी संसद में हमारी पूर्व सांसद को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुये अपमानित किया था, उस वक्त भाजपा के संस्कार कहां गये थे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता अब हर गली-चौराहे पर भाजपा से सवालों के जवाब मांगेगी ।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अभय सिंह चौहान के लिए एम बी प्रिंटर्स, सी 74 सुदर्शन पूरा, जयपुर से मुद्रित एवं 1ए देवी नगर विस्तार, देवी नगर गली नं. 6 जयपुर 302019 से प्रकाशित। सम्पादक : अभय सिंह चौहान,
मोबाइल : 9314505000 (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार) संपादक : खलील कुरैशी, मोबाइल : 7891542929